देश के चौमुखी विकास के लिए मोदी सरकार अग्रसर ... 24

भारत को दुनिया का कंटेंट उपमहाद्वीप बनाने का लक्ष्य.... 34

01 अप्रैल 2022, ₹ : 20

पॉलिटिकल ट्रस्ट

हिन्दी मासिक

DELHIN/2019/78561

आजादी के अमृत महोत्सव के तर्ज पर बिहार दिवस

वर्ष : 03 अंक : 05, दिल्ली

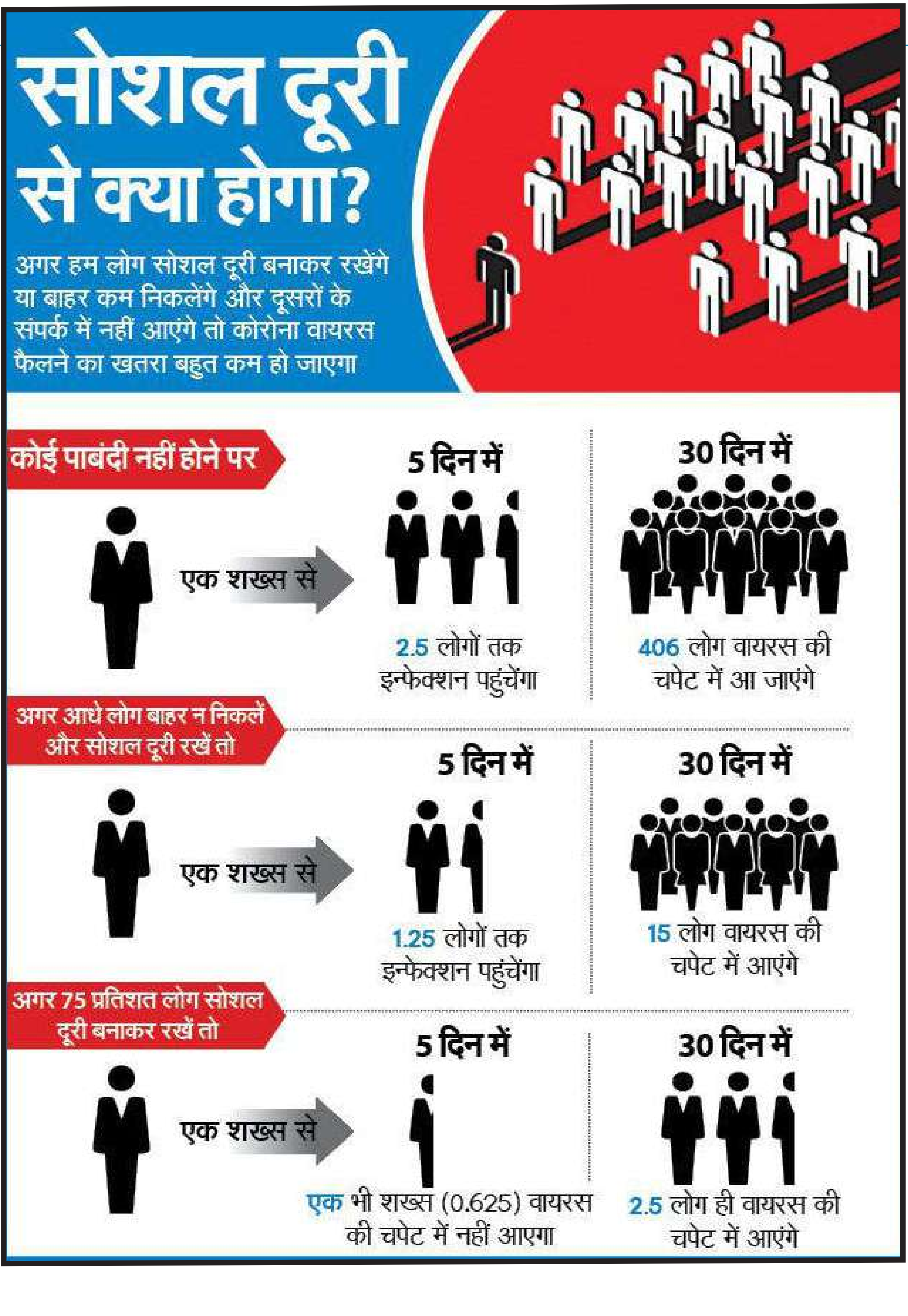
सोशल दूरी से क्या होगा?
अगर हम लोग सोशल दूरी बनाकर रखेंगे या बाहर कम निकलेंगे और दूसरों के संपर्क में नहीं आएंगे तो कोरोना वायरस फैलने का खतरा बहुत कम हो जाएगा
कोई पाबंदी नहीं होने पर
एक शख्स से
5 दिन में
2.5 लोगों तक इन्फेक्शन पहुंचेगा
30 दिन में
406 लोग वायरस की चपेट में आ जाएंगे
अगर आधे लोग बाहर न निकलें और सोशल दूरी रखें तो
एक शख्स से
5 दिन में
1.25 लोगों तक इन्फेक्शन पहुंचेगा
30 दिन में
15 लोग वायरस की चपेट में आएंगे
अगर 75 प्रतिशत लोग सोशल दूरी बनाकर रखें तो
एक शख्स से
5 दिन में
एक भी शख्स (0.625) वायरस की चपेट में नहीं आएगा
30 दिन में
2.5 लोग ही वायरस की चपेट में आएंगे

पॉलिटिकल ट्रस्ट

वर्ष : 03 , अंक : 05 , 01 अप्रैल 2022

E-mail : infoptrust19@gmail.com

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक क्षेत्रों ...

बीआरओ पर्यटन पोर्टल का उद्घाटन ...

भारतीय राजनीति में तेजी से उभर ...

विविध पृष्ठ संख्या

विविध	पृष्ठ संख्या
संपादकीय	6
यूपी की जनता ने बाबा का किया अभिनंदन	7
आजादी के अमृत महोत्सव के तर्ज पर बिहार दिवस	9
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक क्षेत्रों में आमूलचूल ...	16
बीआरओ पर्यटन पोर्टल का उद्घाटन	20
दलबदलुओं को जनता ने अच्छा सबक सिखाया	22
देश के चौमुखी विकास के लिए मोदी सरकार अग्रसर ...	24
अपने मूल जड़ों व लोक संस्कृति से जुड़ा समाज, ...	25
कंस्टीट्यूशन क्लब में स्वर्गीय ललित मोहन मिश्रा ...	26
आईआईटी से नियोक्ता और उद्यमी निकलेंगे, कर्मचारी ...	27
धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान लॉंच	29
भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र मजबूत होकर उभर रहा	32
भारत को दुनिया का कंटेंट उपमहाद्वीप बनाने का लक्ष्य	34
देवभूमि उत्तराखण्ड से होगी समान नागरिक संहिता ...	36
भारतीय राजनीति में तेजी से उभर रही आम आदमी पार्टी	38
52 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास	40
मारवाह स्टूडियोज में नम आंखों से याद किया गया ...	42
टूटते-झड़ते बालों की समस्याओं के घरेलू उपाय	43
बदरीनाथ धाम में मौजूद है यह बेहद पवित्र झरना, पाप ...	44
तरबूज है सेहत का खजाना, इसके ये हैं 8 चमत्कारी ...	45
सामाजिक विषयों पर बनी फिल्में राष्ट्र निर्माण में ...	46
सोमी ने ऐश्वर्या राय को लेकर किया बड़ा खुलासा	48
प्रेग्नेंट देबिना बनर्जी ने अनारकली सूट में बिखेरे जलवे	49
'माई' नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज	50

नोट : प्रकाशित लेखों में प्रकाशक एवं संस्थान की सहमति होना आवश्यक नहीं है, प्रस्तुत लेख लेखकों के अपने व्यक्तिगत विचार, राय हो सकते है। सभी तरह के वाद – विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

पृष्ठ सज्जा : शर्मा कम्प्यूटर्स, शकरपुर, दिल्ली–92

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक कुमारी निम्मी द्वारा मासिक पत्रिका **'पॉलिटिकल ट्रस्ट'**, एफ–92, टॉप फ्लोर, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली से प्रकाशित एवं ग्राफिक प्रिंट, 383, एफ आई ई, ग्राउंड फ्लोर, पटपडगंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली से मुद्रित।

पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते मूल्य

कोरोना महामारी से उबर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को जिस तरह यूक्रेन संकट का सामना करना पड़ा, उसके नतीजे में महंगाई बढ़नी ही थी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि से दुनिया के अन्य देशों की तरह

भारत भी जूझ रहा है। चूंकि भारत अपनी खपत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए उस पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ा है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि पेट्रोलियम पदार्थो के मूल्यों में वृद्धि का सिलसिला कब थमेगा, लेकिन यदि वह थमा नहीं तो महंगाई की चुनौती और अधिक गंभीर होना तय है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि महंगाई यूक्रेन संकट के पहले से ही सिर उठा रही थी, क्योंकि कोरोना पर लगाम लगने के कारण खपत में वृद्धि हो रही थी और उसके चलते अनेक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कहना सही है कि भले ही यूक्रेन युद्ध दुनिया के एक कोने में लड़ा जा रहा हो, लेकिन सभी देशों पर उसका असर कुछ वैसे ही पड़ रहा है, जैसे कि कोरोना महामारी का पड़ा, लेकिन समस्याओं का उल्लेख करने मात्र से वे हल होने वाली नहीं हैं।

सरकार को ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे यूक्रेन संकट से उपजी परिस्थितियों के प्रभाव को कम किया जा सके। यह ठीक है कि सरकार के पास सीमित विकल्प हैं, लेकिन उसे जो कुछ संभव हो, वह तो करना ही होगा। रिजर्व बैंक को भी यह देखना होगा कि वह अपने स्तर पर क्या कर सकता है? सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि खाने-पीने की सामग्री के साथ अन्य अनेक वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं और इससे आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि कच्चे तेल के दामों में वृद्धि कब तक जारी रहेगी, इसलिए सरकार को वैकल्पिक उपायों की तलाश करनी चाहिए। इस क्रम में उसे यह भी देखना होगा कि आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कैसे घटाई जाए? उसे अपने ऊर्जा हितों को सुरक्षित करने के जतन भी करने होंगे।

बंगाल में विधायकों के बीच हुई हिंसक झड़प

बंगाल विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हुई हिंसक झड़प यही बता रही है कि ममता सरकार बीरभूम की दिल दहलाने वाली घटना पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। यह भी किसी से छिपा नहीं कि वह इस घटना की सीबीआइ जांच भी नहीं चाह रही थी। जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए एक तरह से उसे धमकी ही दी कि अगर जांच सही तरीके से नहीं की गई तो वह सड़कों पर उतरेंगी। यदि कलकत्ता उच्च न्यायालय को बंगाल पुलिस पर भरोसा होता तो वह घटना की जांच सीबीआइ के हवाले करता ही क्यों? यहां यह भी ध्यान रहे कि इसी उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनावों के बाद हुई भीषण हिंसा की जांच इसीलिए

सीबीआइ को सौंपी थी, क्योंकि बंगाल पुलिस ने उस दौरान हिंसक तत्वों की घोर अनदेखी की थी। यह अनदेखी बीरभूम की घटना के मामले में भी देखने को मिल रही और कोई भी समझ सकता है कि इसी कारण तृणमूल कांग्रेस यह नहीं चाह रही थी कि विधानसभा में इस विषय पर चर्चा हो। आखिर बीरभूम की जिस भयावह घटना ने सारे देश को झकझोर दिया हो, उस पर विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए थी? इससे खराब बात और कोई नहीं कि सत्तापक्ष के सदस्यों ने न केवल चर्चा से इन्कार किया, बल्कि चर्चा की मांग कर रहे भाजपा विधायकों से मारपीट भी की। आम तौर पर विधायी सदनों में हंगामा, धक्कामुक्की और मारपीट करने का आरोप विपक्ष पर लगता है, लेकिन बंगाल विधानसभा में इस आरोप के दायरे में सत्तापक्ष के सदस्य भी हैं। यह बात और है कि इस हिंसा के लिए केवल भाजपा विधायकों को जिम्मेदार माना गया और उनमें से पांच को साल भर के लिए निलंबित भी कर दिया गया। यह मनमानी के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के भाजपा विधायकों के साल भर के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया था।

समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों ?

सभी मत-मजहब वालों के लिए तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, विवाह की आयु, बच्चों को गोद लेने और विरासत संबंधी नियम एकसमान बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इन सभी मामलों में एक जैसे नियम बन जाते हैं तो समान नागरिक संहिता का उद्देश्य

पूरा हो जाएगा। होना तो यह चाहिए था कि अभी तक इस उद्देश्य को हासिल कर लिया जाता, क्योंकि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो कुछ दलों के नकारात्मक रवैये, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति और इस दुष्प्रचार के कारण कि इससे विभिन्न समुदायों के रीति-रिवाजों में अनावश्यक हस्तक्षेप होगा। दुर्भाग्य से यह दुष्प्रचार अभी भी जारी है। यह इसके बाद भी जारी है कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालय समय-समय पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता रेखांकित कर चुके हैं। तथ्य यह भी है कि गोवा में समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है और वहां सभी समुदायों के लोग रहते हैं। आखिर जो व्यवस्था गोवा में बिना किसी बाधा के लागू है, वह शेष देश में क्यों नहीं लागू हो सकती? प्रश्न यह भी है कि जब अन्य कई लोकतांत्रिक देशों में समान नागरिक संहिता लागू है तो भारत में उसका विरोध क्यों होता है? यह प्रश्न अनुत्तरित है तो इसीलिए कि अभी तक किसी सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तक तैयार करने की जहमत नहीं उठाई। कम से कम अब तो यह काम होना ही चाहिए, ताकि उस पर व्यापक विचार-विमर्श हो सके। यह हास्यास्पद है कि एक ओर संविधान की दुहाई देकर यह कहा जाता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और दूसरी ओर भिन्न-भिन्न समुदायों के लिए विवाह विच्छेद, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियम अलग-अलग बने हुए हैं। समान नागरिक संहिता के अभाव के चलते ही विभिन्न समुदायों के लोगों में आपसी एकता का वह भाव देखने को नहीं मिलता, जो आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।

अब गाँधी परिवार को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए

कांग्रेस को संचालित करने के तौर-तरीकों से नाखुश नेताओं का समूह अपनी सक्रियता बनाए हुए है। इस सक्रियता के बीच पार्टी नेतृत्व यानी गाांधी परिवार ने चुनाव वाले राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से त्यागपत्र मांग लिए। इससे यही साबित हुआ कि गाांधी परिवार पांच राज्यों में पार्टी की पराजय के लिए अपनी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हैरानी यह है कि कोई भी कांग्रेसी नेता ऐसा कुछ कहने को तैयार नहीं कि चुनाव वाले राज्यों में जब सारे फैसले परिवार के लोगों यानी सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने लिए, तो फिर हार का ठीकरा राज्य अध्यक्षों पर क्यों फोड़ा जा रहा है? जहां चुनाव के चार-पांच महीने पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पहल पर पंजाब

में मुख्यमंत्री बदला गया, वहीं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की ओर से उन सारे बड़े नेताओं को किनारे कर दिया गया, जो राज्य में कुछ असर रखते थे। क्या यह आवश्यक नहीं था कि सोनिया, राहुल और प्रियंका कम से कम हार की जिम्मेदारी लेने की घोषणा करते? उनके रवैये से यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वे पार्टी पर अपनी पकड़ ढीली करने वाले नहीं और पांच राज्यों में हार की समीक्षा के नाम पर लीपापोती ही होने वाली है। आश्चर्य नहीं कि इस बार भी पिछले मौकों की तरह हार की समीक्षा तो की जाए, लेकिन उससे कोई सबक न सीखे जाएं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी तक वह एंटनी रपट सामने नहीं आ सकी है, जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद तैयार किया गया था। यह तो समय ही बताएगा कि जी-23 समूह के नेताओं की सक्रियता के क्या नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि समस्या केवल इतनी भर नहीं है कि गाांधी परिवार मनमाने तरीके से फैसले ले रहा है, बल्कि यह भी है कि कांग्रेस ऐसा कोई एजेंडा नहीं पेश कर पा रही है, जिससे देश की जनता उसकी ओर आकर्षित हो सके। यदि कल को जी-23 नेताओं के दबाव में गाांधी परिवार पार्टी पर अपनी पकड़ ढीली कर दे या फिर सामूहिक नेतृत्व की उनकी मांग को पूरा कर दे, तो भी बात बनने वाली नहीं है।

संपादकीय

कुमारी निम्मी
संपादक 'पॉलिटिकल ट्रस्ट'

आम आदमी पार्टी ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर भगवंत मान के लिए जो एक नई शुरुआत की है। शपथ लेने के बाद राज्य के साथ-साथ देश की भी निगाह नए मुख्यमंत्री पर रहेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना इसलिए एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, क्योंकि कांग्रेस, भाजपा और वाम दलों के बाद वह चौथा ऐसा दल है, जो एक के बाद दूसरे राज्य की सत्ता में पहुंचा है। उसकी इस सफलता ने उन तमाम क्षेत्रीय दलों के सामने एक चुनौती पेश कर दी है, जो एक लंबे अर्से से राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं।

यह विशेष उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी अपने गठन के दस वर्ष के अंदर ही दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता तक पहुंच गई। उसने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पंजाब में केवल शानदार जीत ही हासिल नहीं की, बल्कि चुनावी मुकाबले में प्रतिद्वंद्वी दलों के बड़े-बड़े दिग्गजों को पराजित किया और वह भी अपने आम उम्मीदवारों के सहारे। उसने कुछ ऐसा ही करिश्मा दिल्ली में भी किया था।

पंजाब के चुनाव नतीजों ने यही बताया कि राज्य के लोग कांग्रेस एवं शिरोमणि अकाली दल, दोनों से आजिज आ चुके थे और उन्हें बेहतर विकल्प के रूप में केवल आम आदमी पार्टी ही नजर आई। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि आम आदमी पार्टी की सफलता में केजरीवाल शासन के दिल्ली माडल ने एक बड़ी भूमिका अदा की, जो लोगों के कल्याण पर जोर देता है। वास्तव में यही इस दल की राजनीति का केंद्रीय बिंदु है।

चूंकि दिल्ली के मुकाबले पंजाब एक पूर्ण राज्य है इसलिए भगवंत मान सरकार के पास फैसले लेने की पूरी छूट होगी। यह स्थिति एक अवसर भी है और चुनौती भी। चुनौती इसलिए, क्योंकि पंजाब कई गंभीर समस्याओं से दो-चार है। एक समय पंजाब की गिनती देश के सबसे संपन्न राज्य में होती थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में वह पिछड़ गया है।

पंजाब को केवल आर्थिक संकट से ही उबारने की चुनौती नहीं है। इसके साथ ही उसे उस खतरे से भी बचाने की चुनौती है, जो सीमावर्ती राज्य होने के नाते उस पर मंडरा रहा है। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भगवंत मान को बधाई देते हुए उनकी सरकार को हर तरह का सहयोग देने का वादा किया।

यूपी की जनता ने बाबा का किया अभिनंदन

जनता ने पूर्व में प्रदेश में रही अन्य सरकारों के कार्यकाल की तुलना करके, उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त, चौबीस घंटे बिजली युक्त, विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले योगी राज, सुशासन, राष्ट्रवाद और योगी की विशेष कार्यशैली को वोट देकर विजयी बनाया है।

अतुल ठाकुर

देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम 10 मार्च को आ चुकें है, इन चुनाव परिणामों में भाजपा ने चार राज्यों में एकबार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल करके अपना जलवा कायम रखा है। वैसे देखा जाए तो पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीति में रुचि रखने वाली देश की अधिकांश जनता कि निगाहें हर पल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर ही लगी हुई थी। देश विदेश के अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों व कुछ लोगों का यह मानना था कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में कोरोना काल की ज्वलंत समस्याओं, रोजी-रोटी, लंबे समय तक चले किसानों के आंदोलन का बहुत ही व्यापक असर योगी सरकार के विरोध में देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में जब चुनाव परिणाम आए तो योगी ने प्रचंड बहुमत 255 सीटों के साथ चुनावों में विजय हासिल करके बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्यचकित करने का कार्य कर दिया है। हालांकि

जो लोग धरातल पर जाकर पूरे चुनावी घमासान को नजदीक से देख रहे थे उनके सामने यह स्पष्ट था कि अबकी बार उत्तर प्रदेश में योगी एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में बनकर उभर रहे हैं, लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हीं के नाम से प्रभावित होकर जाति-धर्म व दलगत राजनीति के बैरियर तोड़कर भाजपा को वोट करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि इस बार जन अदालत में बुलडोजर वाले बाबा के नाम से मशहूर हो चुके योगी आदित्यनाथ के प्रति जबरदस्त रूप से दिवानगी देखने को मिली है, योगी की बेहद ईमानदार मेहनती सख्त प्रशासक की छवि, अपराधियों के प्रति सख्त कार्यवाही करने की उनकी कार्यशैली ने मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को बेहद आकर्षित करने का कार्य किया है। जिससे चुनावी रणभूमि में भाजपा से नाराज़ होने वाले मतदाताओं की बड़ी भरपाई धरातल पर हुई है।

हालांकि किसी भी स्तर के चुनावों में विजय ईमानदारी से सामुहिक सहयोग के बलबूते ही संभव है, उसी ने 37 वर्ष के बहुत लंबे अरसे बाद उत्तर प्रदेश में लगातार दोबारा फिर से किसी पार्टी की सरकार को बनने का अवसर प्रदान किया है। वैसे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रणभूमि में दिन-रात एक करके मेहनत की वह बेहद काबिले तारीफ है। भाजपाइयों के लिए उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाजपा की जीत योगी की उस मेहनत का ही एक सकारात्मक सुखद परिणाम है, जिसका आनंद आज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता व छोटे-बड़े नेता लेने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों के द्वारा बहुत सारे लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली भाजपा की विजय का श्रेय सबसे अधिक योगी आदित्यनाथ को ही जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आम जनता के बीच इस बार योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पक्ष व विपक्ष दोनों तरफ एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गयी थी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव योगी आदित्यनाथ की छवि के इर्द-गिर्द ही लड़ा गया था, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के एक बहुत बड़े वर्ग ने भी उनकी फायरब्रांड बुलडोजर वाले बाबा वाली छवि के चलते ही भाजपा को वोट देकर जिताने का कार्य किया है। भाजपा को चुनाव रण में वर्ष 2022 की सबसे बड़ी चुनावी जीत योगी के चेहरे की ही देन है। जनता की ताकत के बलबूते योगी आदित्यनाथ को पुनः प्रदेश की कमान संभालने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा की सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त किया है।

जनता ने पूर्व में प्रदेश में रही अन्य सरकारों के कार्यकाल की तुलना करके, उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त, चौबीस घंटे बिजली युक्त, विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले योगी राज, सुशासन, राष्ट्रवाद और योगी की विशेष कार्यशैली को वोट देकर विजयी बनाया है।

जनता ने उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराध, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, परिवारवाद, अवसरवाद और अलगाववाद को पराजित करने के महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने के लिए पार्टी के नियम कायदे कानून से ऊपर उठकर एकबार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को भारी बहुमत देकर उनका चयन किया है, हालांकि यह तो आने वाला समय ही तय करेगा कि अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जन आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरेंगे, लेकिन प्रदेश के निवासियों को उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं।

बिहार में प्रधानमंत्री मित्र मेगा टैक्सटाइल पार्क के लिए पूरी मदद करेंगे। बिहार में टेक्सटाइल व अन्य उद्योगों को खड़ा करने के लिए केंद्र से पूर्ण सहयोग मिलेगा। बिहार में अपार संभावनाएं हैं और कुछ कर दिखाने का माद्दा है। यह बातें भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार दिवस के मौके पर दिल्ली हाट में आयोजित बिहार उत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर कही।

आईएनए दिल्ली हाट में बिहार दिवस के मौके पर भव्य बिहार उत्सव का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया और मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार में बिहार से कई मंत्री और सांसद शामिल हुए। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में दिल्ली हाट में आयोजित बिहार उत्सव कार्यक्रम में केंद्र सरकार के जो मंत्री शामिल हुए उनमें शामिल हैं केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय इस्पात मंत्री आर.सी.पी सिंह, केंद्रीय खाद्य

एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ।

बिहार उत्सव कार्यक्रम में संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे कई सांसद भी शामिल हुए। बिहार उत्सव में शामिल होने वाले प्रमुख नाम रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रामकृपाल यादव, राज सभा सांसद गोपाल नारायण सिंह, कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, जहानाबाद सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद, सांसद मोहम्मद जावेद, अररिया सांसद प्रदीप सिंह, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, शिवहर सांसद रमा देवी, झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल, गया से सांसद विजय कुमार मांझी, नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार, जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, विधान परिषद सदस्य संजय मयूख व अन्य।

उद्घाटन समारोह एवं अतिथियों द्वारा बिहार के नायाब व उत्कृष्ट हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा उत्पादों के स्टॉलों के परिभवन एवं अतिथियों के संभाषणों के बाद सांस्कृतिक संध्या में मशहूर गायक व सांसद मनोज तिवारी ने अपनी प्रस्तुती से सभी को मंत्र-मुग्ध कर दिया।

केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार स्थापना दिवस समारोह पर बोलते हुए कहा कि बिहार अब प्रचुण क्षमताओं वाला राज्य है। बिहार की क्षमता का अभी भी सही मायने में इस्तेमाल नहीं हुआ है। परिवर्तन का बिगूल जब-जब बजा है वो बिहार से ही बजा है। अब वह चाहे सत्याग्रह आदोंलन का बिगुल हो, जिसे महात्मा गांधी ने चंपारण से शुरु किया या फिर आपातकाल के खिलाफ संपूर्ण क्रांति हो, जिसे भारत रत्न जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार से ही शुरु किया गया। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि वर्षों-वर्षों तक जो विकास से वंचित है, उस पूर्वोंचल का विकास करना है। बिहार अब उद्योग और टेक्सटाइल के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। बिहार की क्षमता को अभी भी पुरी दुनिया ने ठीक पहचाना नहीं है। लीची और आम बिहार और देश के साथ अब दुनिया में भी पहुंच रहा है। मैं सभी बिहारवासियों का ऋणी हूं। आज आप रेलवे स्टेशन पर मधुबनी पेंटिंग बनी हुई देख सकते हैं, इससे सुंदर और क्या हो सकता है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिहार उत्सव समारोह में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार से मेरा विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि हमने बिहार वासियों को पूरे देश में अपनी पहचान के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम करते हुए देखा है और पूरा भरोसा है बिहारी अपने दम पर अपने राज्य के साथ साथ देश को भी नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं।

बिहार उत्सव 2022 पर केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जय बिहार सभी भाईयों को, आज

में एक ही आग्रह करूंगा कि 'कपड़ा तो सब पहने ला छलकावे ला कोई कोई', ऐसे ही बिहार को अब देश का टेक्सटाइल हब बनाना है यही मेरी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह है।

केंद्रीय इस्पात मंत्री आर.सी.पी सिंह ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा दुनिया का इतिहास बिहार का इतिहास है। पहले गणतंत्र वैशाली में आया। बिहार का इतिहास बहुत समृद्ध है। मगध का जामाना देखिए बिहार में, इतिहास में बिहार सत्ता, ज्ञान का केंद्र रहा है। बिहार की जमीन की कोई तुलना नहीं है। हमें फिर से बिहार को बिहार बनाना है।

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पहले बिहार की जय हो का नारा बुलंद किया। फिर कहा कि एक बिहारी 100 पर भारी है और एक और एक मिलाकर 11 बिहारी हो जाते हैं। बिहार सबसे निराला है और आने वाले दिनों में बिहार सभी से आगे निकलेगा।

बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा दिल की गहराइयों से स्थापना दिवस पर पधारे सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद का स्वागत करता हूं। यह बात मेरे दिल में घर कर गई है। अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर में स्थित चंपारण में मेगा टेक्सटाइल मैत्री पार्क के लिए 1719 एकड़ की जमीन का अलोटमेंट हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में यह बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। मेगा औद्योगिक पार्क के निर्माण से बिहार अब विकास की राह पर नया कृतिमान स्थापित करते हुए पूर्वांचल भारत का औद्योगिक हब के रूप में अपनी पहचान बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। बिहार उत्सव 2022 से जुड़ी जानकारी देते हुए बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि इस बार बिहार दिवस का समारोह भी आजादी के अमृत महोत्सव के तर्ज पर ही किया जा रहा है। इस वर्ष बिहार दिवस का विषय जल जीवन हरियाली पर आधारित है। जिससे सभी को जल जीवन हरियाली के तहत बिहार में किए जा रहे विकास के बारे में अवगत करवाया जाएगा।

बिहार स्थापना दिवस के एवं बिहार उत्सव के उद्घाटन के बाद आयोजित संस्कृतिक संध्या में मशहूर गायक व सांसद मनोज तिवारी ने अपने संगीतों की प्रस्तुति से लोगों का उत्साह वर्धन किया। सांस्कृतिक संध्या में मनोज तिवारी के अलावा मशहूर लोक गायिका विजया भारती और स्वर्णिम कलाकेंद्र मुज़फरपुर द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी-अपनी प्रस्तुति दी। जिससे बिहार उत्सव 2022 के समारोह में चार चादं लग लगा।

बिहार उत्सव 2022 के मौके पर सभी को संबोधन करते हुए बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इस मौके पर सभी बिहार वासियों और बिहार वासियों के मित्रों को धन्यवाद किया। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा मेक इन बिहार अब मेक इन ईंडिया के तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा अब बिहार का मकसद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के

नेतृत्व में बिहार में स्थापित उद्योग से बने उत्पादों को देश के कोने-कोने तक पहुंचाना।

आई.एन.ए. दिल्ली हाट में 59 से अधिक बिहार के हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे। इसमें मुख्य रुप से बिहार के हैंडलूम उत्पाद के 21 स्टॉल, 9 स्टॉल मधुबनी पेंटिंग, 3 स्टॉल लेदरक्राफ्ट, 2 स्टॉल सुजनी क्राफ्ट, 2 स्टॉल लाह शिल्प, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मखाना और बंबू क्राफ्ट आदि के स्टॉल लगे हुए थे।

'बिहार उत्सव 2022' में आए सभी महानुभावों ने स्वादिष्ट बिहारी व्यंजनों का भर-पूर स्वाद लिया। इस दौरान लिट्टी चोखा से लेकर दही जलेबी तक तरह-तरह के सुप्रसिद्ध बिहारी व्यंजन खाने का स्टॉल लगा हुआ था।

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत आई.एन.ए दिल्ली हाट में 16 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक 'बिहार उत्सव प्रदर्शनी' का आयोजन किए जा रहा है। सभी देशवासियों से बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने आग्रह किया कि वह जरुर अपना समय निकाल कर यहां आएं और बिहार के चौ-तरफा उद्भव के साक्षी बनें।

प्रधान सचिव. संदीप पौण्डरीक, उद्योग विभाग, बिहार ने बिहार उत्सव के समापन पर सभी माननीय अतिथियों को धन्यवाद किया।

'बिहार उत्सव 2022' के इस अवसर पर बिहार उद्योग मंत्रलायल से उद्योग निदेशक रुपेश कुमार श्रीवास्तव, बीयाडा के ई. डी. भोगेंद्र लाल, बिहार सरकार के उप उद्योग निदेशक सह मेला प्रभारी बिशेश्वर प्रसाद, संजय श्रीवास्तव, विभाग के सुधांषु भूषण कुमार, गौतम कुमार, संजीत कुमार, रवि शंकर कुमार, अजय कुमार आदि उपस्थित रहें।

बिहार का गौरवशाली वर्तमान विकास के पथ पर अग्रसर

बिहार पर्यावरण संरक्षण के मामले में देश से 30 साल आगे है भारत नेअपने कार्बन उत्सर्जन को 2070 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य किया है ग्लासगो में पिछले साल हुए जलवायु सम्मेलन कॉप26 मे भारत के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी लेकिन बिहार अपने कार्बन उत्सर्जन को 2040तक ही नेट जीरो करने की योजना बना रहा है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जल जीवन हरियाली जैसा बड़ा अभियान शुरू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है संयुक्त राष्ट्र के कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ग्लोबल क्लाइमेट लीडर पुकारा गया और जल जीवन हरियाली अभियान को दुनिया के लिए पथप्रदर्शक माना गया यह बातें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के भारत प्रमुख एवं पर्यावरणविद् अतुल बगई ने मंगलवार को बिहार दिवस के अवसर पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बिहार का गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान में विकास के पथ पर अग्रसर बिहार विषय पर आयोजित परिचर्चा में कहीं। परिचर्चा का आयोजन बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया था इसमें बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा मुख्य अतिथि थे ।

पर्यावरणविद अतुल बगई ने जानकारी दी थी दिसंबर 2021 में पटना में एक मीटिंग हुई थी जिसमें 20 विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया था कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में बिहार को 2040 तक नेट जीरो करने के

लिए एक कारगर नीति बनाएं।

श्री अतुल बगई ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न संकट पूरी दुनिया और मानव जाति के लिए गंभीर चुनौती है संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर 24 सितंबर 2020 को हुए इंटरनेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए भारत में सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में उन्हें ग्लोबल क्लाइमेट लीडर कहा गया और जल जीवन हरियाली अभियान को दुनिया के लिए प्रदर्शन माना गया इससे पहले नवंबर 2019 में बिहार दौरे पर आए बिल गेट्स ने भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन तथा जल जीवन हरियाली अभियान की मुक्त कंठ से तारीफ की थी श्री अतुल बगई ने कहा कि जल संरक्षण और हरित आवरण में वृद्धि के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 11 बिंदुपर आधारित कार्य योजना तैयार कर उसे राज्य भर में मिशन मोड में लागू किया जा रहा है इसके तहत जल संसाधनों को पुनर्जीवित किया जा रहा है और हर 7 करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं इस अभियान पर चरणबद्ध तरीके से कुल 24 524 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है ।

बिहार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोटर की सराहना करते

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2005 में बिहार की सत्ता संभाली थी तब से अब तक कुल 196 महीनों में नीतीश कुमार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बिहार के नवनिर्माण के प्रतीक के रुप में परिचर्चा से पहले मंत्री संजय कुमार झा एवं अन्य अतिथियों ने मिलकर 196 रंग-बिरंगे हीलियम गुब्बारे हवा में छोड़े बताया गया कि यह गुब्बारे नए बिहार की विकास की उड़ान के प्रतीक हैं और बिहार वासियों के उत्साह उमंग जोश और जुनून के प्रतीक है इस मौके पर गायक सत्येंद्र संगीत एवं अन्य कलाकारों ने बिहार के राज्य गीत के गायन के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया

हुए श्री अतुल बगई ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा हरित आवरण बढ़ाने जल के संरक्षण और प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदम अत्यंत सराहनीय है। झारखंड से बिहार के बंटवारे के बाद बिहार का हरित आवरण 9% रह गया था वष् 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना की गई और 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया।

इसके तहत लगभग 22 करोड से अधिक पौधे लगाए गए हैं अब राज्य का हरित आवरण 15% से अधिक हो चुका है बिहार सरकार ने इसे 17% से अधिक रखने का लक्ष्य रखा है । परिचर्चा में मुख्य अतिथि विहार के सूचना एवं जनसंपर्क तथा जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मॉडल देश दुनिया के लिए नजीर है नीतीश कुमार की दृष्टि स्पष्ट है पृथ्वी पर जब तक जल और हरियाली है तभी तक जीवन सुरक्षित है।

श्री संजय कुमार झा ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एक अवयव है जल के अधिशेष वाले क्षेत्र से जल को जल संकट वाले क्षेत्र में ले जाना। इसके तहत बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना का पहली बार कार्यान्वयन किया जा रहा है इस योजना के तहत मॉनसून के महीनों में गंगा नदी के अधिशेष जल को लिफ्ट कर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चार शहरों- गया बोधगया राजगीर और नवादा में पहुंचाया जाएगा वहां सालों भर पेयजल रूप में उपयोग किया जाएगा।

श्री संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचने से किसी क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से एक नई ताकत मिलेगी। इसके लिए जल संसाधन एवं कृषि सहित पांच विभागों के पदाधिकारियों के संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण दलों के द्वारा राज्य के प्रत्येक ग्राम तथा टोले के असिंचित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया गया है।

सर्वेक्षण में जिन योजनाओं को चिन्हित किया गया है उन्होंने राज्य के 7 लाख 79 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने की संभावना बन रही है इसमें आहार पईन ,जल अधिशेष क्षेत्र से पानी उठाकर और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ले जाने का काम, चेक डैम ,एंटी फ्लड सलूइस, नहरो का पुनस्थापन, विस्तारीकरण, नलकूप आदि प्रकार की योजनाएं है जिनका क्रियान्वयन उकत पांचो विभागों के द्वारा प्रारंभ किया जाना है ।

श्री संजय कुमार झा ने कहा कि दुनिया भर के अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत है की आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने और नए रोजगार के सृजन के लिए सुगम यातायात तथा बिजली की पर्याप्त उपलब्धता पहली शर्त है । नया बिहार इस शर्त को पूरा करते हुए विकास की एक नई उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ फेज में है पूरे

बिहार में सड़क रेल और हवाई कनेक्टिविटी के साथ सुलभ संपर्क करता है । राज्य के कोटे में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। कभी अपहरण के लिए बदनाम रहे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति निरंतर बेहतर हुई है। इस नए बिहार में उद्योग, आईटी सेवाओं ,शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएं है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव एवं बिहार काडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई हर घर नल का जल पहुंचाने की योजना बिहार की वर्तमान और आने वाली वीडियो की बेहतर स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है

बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में व्यापक प्रयास किए गए हैं वर्ष 2006 में कराए गए एक सर्वेक्षण में पता चला था कि बिहार के प्रखंड स्तर के अस्पतालों में प्रतिमाह औसतन 39 लोग इलाज कराने पहुंचते थे सुविधाओं में निरंतर वृद्धि के कारण अब प्रखंड स्तर के अस्पतालों में हर माह औसतन 10,000 से अधिक लोग अपना इलाज करा रहे हैं ।वरिष्ठ पत्रकार एवं द प्रिंट के राजनीतिक संपादक डीके सिंह ने कहा कि बिहार जैसी सघन आबादी वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कृषि मुख्य सहारा है जो खाद्य ,सुरक्षा ,रोजगार और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र की औसत वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक रही है ।इस दौरान प्रमुख अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बिहार को केंद्र सरकार से 5 बार प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार हासिल हो चुका है तीन कृषि रोडमैप को जमीन पर सफलतापूर्वक उतारने के कारण बिहार में कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह ने कहा कि बिहार देश का सबसे सघन आबादी वाला प्रदेश है। प्रदेश में है वित्तीय संसाधनों सीमित उपलब्धता और ढेर सारी चुनौतियों के बावजूद पिछले डेढ़ दशक में बिहार की औसत विकास दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक रही है और इसे देश का ग्रोथ इंजन कहा जाने लगा है।

बिहार इस समय प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 3,0 86 किमी पथ घनत्व के साथ देश में तीसरे स्थान पर है । पथ घनत्व का राष्ट्रीय औसत 1,6 17 किलोमीटर प्रति ऍकहजार वर्ग कीमी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में ना सिर्फ ढांचागत सुविधाओं का व्यापक विकास हुआ है बल्कि महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार की दिशा में भी अनेक उल्लेखनीय पहल की गई है। समारोह को कई अन्य विशिष्ट वक्ताओं ने संबोधित किया अतिथियों का स्वागत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के निदेशक कंवल तनु जी ने किया। समारोह में अनेक वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर और बुद्धिजीवी मौजूद थे

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन

संजय सिंह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में चंडीगढ़ पुलिस आवासीय परिसर, धनास के प्रथम चरण का लोकार्पण व तीसरे चरण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चण्डीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित, चण्डीगढ़ की महापौर सुश्री सरबजीत कौर और केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सभी सरकारी विभागों में सबसे कठिन होती है। पुलिसकर्मी एकमात्र ऐसा सरकारी कर्मचारी होता है जिसके ड्यूटी के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। उसे लगातार, दिन-रात समस्या के साथ जूझना पड़ता है और अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। क़ानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की ज़रूरत उस वक़्त सबसे ज़्यादा होती है जब पूरा देश आनंद और उत्साह के साथ अपने परिवार के साथ त्यौहार मना रहा होता है। होली, रक्षाबंधन, दीपावली, लोहड़ी के दिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कई गुना बढ़ जाती है और उनिहें अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाने का मौक़ा नहीं मिलता। काम के घंटे विपरीत होने के कारण उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है, खान-पान और व्यायाम नियमित नहीं हो पाती। ऐसे समय में अपने परिवार के साथ जितना भी समय एक अच्छे माहौल में पुलिसकर्मी बिता सके, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज अलग-अलग स्तर पर लगभग 1560 परिवारों में से 350 परिवारों को उनका निवास भी मिल गया है। उन्होंने कहा कि हाऊसिंग सेटिस्फ़ेक्शन रेश्यो देशभर का पुलिसकर्मियों की दक्षता बढ़ाने के सभी प्रयासों में ना केवल एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बल्कि एक चुनौती भी है। जब तक इसे आप नहीं बढ़ाते तब तक पुलिसकर्मी से अपनी ड्यूटी के अच्छे निर्वहन की आप आशा नहीं कर सकते।

अमित शाह ने कहा कि जब तक तकनीक का उपयोग इन्वेस्टिगेशन, डेटा स्टोरेज और इसके एनालिसिस के लिए नहीं करेंगे तब तक अपराध पर नियंत्रण असंभव है। जब तक क्लासीफ़ाइड डेटा नहीं होता है, इसके एनालिसिस के बिना अपराध नियंत्रण की कोई रणनीति नहीं बन सकती। जब तक अन्वेषण को आप स्पीड के साथ नहीं कर सकते, तब तक अपराध पर नियंत्रण नहीं हो सकता। जब तक प्रॉसीक्यूशन की प्रक्रिया साइंटिफ़िक सुबूत के आधार पर नहीं करते हो, तब तक अपराध पर नियंत्रण नहीं पा सकते हो। जब तक प्रॉसीक्यूशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनीटर नहीं कर सकते हो, तब तक आप जल्दी न्याय नहीं दिला सकते हो। ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने आईसीजेएस (ICJS) के माध्यम से देशभर

की पुलिस के लिए रखी हैं। इसके अंतर्गत सीसीटीएनएस में देश के 98 प्रतिशत से ज़्यादा थानों को जोड़ लिया गया है। ई-कोर्ट, ई-प्रिज़न, ई-फ़ॉरेन्सिक और ईप्रॉसीक्यूशन का एक मॉडल बनाया गया है और आईसीजेएस के माध्यम से इन सबको जोड़कर इन्हें थाने तक उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने किया है। लेकिन इन सभी योजनाओं और डेटा का क्या फ़ायदा क्योंकि इनका एनालिसिस तो राज्य या संघ प्रदेश के स्तर पर होना है और इसके आधार पर पुलिस की वार्षिक रणनीति बनानी है, कि हमारे प्रदेश में किस अपराध पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस अपराध की मॉडस ऑपरेंडी क्या है। ये सब राज्यस्तर पर तय करने की ज़रूरत है और बल्कि पुलिस स्टेशन स्तर पर तय करने की ज़रूर है क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में अपराधों का प्रकार, प्रवृत्ति और संख्या अलग-अलग होती हैं। ये सब तभी हो सकता है जब पुलिस थाने के स्तर तक हम आईसीजेएस को पहुंचाएंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली भी आज जारी की गई है। ई-एफ़आईआर रजिस्टर करने की शुरूआत तो हो गई लेकिन जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि थाने जाए बिना एफ़आईआर रजिस्टर हो सकती है।

उन्होंने कहा कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ पुलिस के बीच एक एमओयू हुआ है और मैंने पुलिस कांग्रेस में कई बार कहा है कि जब तक फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर प्रॉसीक्यूशन की प्रक्रिया नहीं होती तब तक दोष सिद्धि की दर को आप सुधार नहीं सकते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि 6 साल से ज्यादा जिसमें सजा है, आने वाले दिनों में हम आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में सुधार करने जा रहे हैं। इसमें इसका प्रोविजन करेंगे परंतु मैन पावर कहां से आएगी, ना देश के पास इतना फॉरेंसिक के क्षेत्र का ट्रेंड मैन पावर है, ना इसकी सुविधाएं हैं। परंतु जब कभी भी शुरुआत करते हैं, दिक्कतें तो आती ही है और दिक्कतों का रास्ता ढूंढना होता है, दिक्कतों से रास्ता बंद हो गया है, अगर ऐसा सोचते हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और यह सभी राज्यों में, क्षेत्रों में अपने एफीलिएटेड कॉलेजों को खोलने वाला है और तब एक बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर उपलब्ध होगी और फिर हम कानूनन यह कर सकेंगे कि 6 साल से ज्यादा जिस भी दफा में सजा है उस सबमें साइंटिफिक एविडेंस को हम कंपलसरी करेंगे।

अभी चंडीगढ़ प्रशासन ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत एक ट्रेंड मैनपावर चंडीगढ़ पुलिस को मिलेगा। जो बच्चे वहां से पास आउट होंगे बीएससी, एमएससी होंगे, कोई फॉरेंसिक के क्षेत्र में एक्सपर्ट होंगे वह चंडीगढ़ पुलिस के साथ सहयोगी बनेंगे और चंडीगढ़ पुलिस अपनी एफ़आईआर, इन्वेस्टिगेशन और प्रशिक्षण में

इसका उपयोग करेगी। मुझे विश्वास है कि इससे चंडीगढ़ पुलिस की दोष सिद्धि की दर में बहुत बड़ी मात्रा में चंडीगढ़ पुलिस को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आज चंडीगढ़ पुलिस का कलेवर बदलने के लिए मोटरसाइकिल और गाड़ियों का आधुनिक संचार सुविधाओं से लैस दस्ता आज दिया गया है। चंडीगढ़ जैसे एक छोटे से संघ प्रदेश के अंदर यह दस्ता जब घूमेगा तब मुझे विश्वास है कि चंडीगढ़ के लोगों में विश्वास के वातावरण बनेगा और इससे पुलिस बल पर भरोसा भी बढ़ेगा और पुलिस को अप्रोच करने का विश्वास भी बढ़ेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा का राजधानी क्षेत्र भी है। यहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति का असर एक संघ प्रदेश और दो राज्यों, यानी तीनों जगह पर पड़ता है। अगर यहां पर चंडीगढ़ पुलिस कोई मॉडल खड़ा करती है तो स्वाभाविक रूप से हरियाणा और पंजाब पुलिस को भी इसका फायदा होता है। आज ये जो नई शुरुआत हुई है इससे न केवल चंडीगढ़, इसके साथ-साथ हरियाणा और पंजाब पुलिस को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर लगभग सवा सौ करोड़ रूपए से ज्यादा राशि चंडीगढ़ पुलिस को अपग्रेड करने के लिए खर्च हुई है और उन सभी का आज लोकार्पण किया गया है। 125 करोड़ रूपए की राशि जिसमें हाउसिंग के प्रोजेक्ट भी है, फॉरेंसिक साइंस को अपग्रेड करने की व्यवस्था भी है और कई सारे ई-इनीशिएटिव भी लिए गए हैं। इससे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा इस संघ प्रदेश को होने वाला है।

अमित शाह ने कहा कि आज एक मानवता का काम हमारे प्रशासक महोदय बनवारीलाल पुरोहित के तत्वाधान में हुआ है। जिन भी कर्मियों ने असमय अपनी जान गंवाई है उन सारे परिवारों की चिंता करते हुए उनको धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है और उनके परिजनों को नौकरी देने का काम भी हो रहा है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि जो जवान ड्यूटी पर तैनात है उसे यह विश्वास होना चाहिए कि प्रशासन चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़ा है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि आज से चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के साथ जोड़ने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि इससे आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो आपकी सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ कर 58 की जगह 60 वर्ष हो जाएगी। महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर के लिए 1 साल की जगह 2 साल की छुट्टी भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि बहुत समय से यह मांग चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी, अधिकारियों की थी और आज मोदी जी ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। कल ही इसका नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा और आप लोगों को नए वित्तीय वर्ष से इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केन्द्र में बनी है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अनेक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन होने की शुरुआत हुई है। परंतु देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत और समस्याविहीन बनाने के लिए और कई दशकों से चली आई

समस्याओं को ख़त्म करने के लिए 7 सालों में जितना काम हुआ है, इतना सात दशकों में कभी नहीं हुआ। चाहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट थिएटर हो, सभी जगह पर जो आतंकवादी समूहों के साथ झड़पों की घटनाओं पर एक प्रभावशाली नियंत्रण हमारे सुरक्षाबलों ने स्थापित किया है। उन्होंने यह संदेश कड़ाई के साथ भेजा है कि देश के नागरिक चाहे नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में रहते हो, कश्मीर में रहते हो, चाहे उत्तर पूर्व में रहते हों, इनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप नक्सलवादी घटनाओं में बहुत कमी आई है, उत्तर पूर्व में कई उग्रवादी संगठनों ने भारत सरकार के प्रोएक्टिव स्टेप को स्वीकार करते हुए भारत सरकार के साथ समझौते किए हैं। नौ हजार से ज्यादा उग्रवादियों ने सरेंडर कर अपने आप को कानून के हवाले किया है। 9,000 से ज्यादा परिवारों ने आज कानून पर भरोसा कर सरेंडर किया है। कश्मीर में भी आतंकवादी घटनाओं पर नकेल कसने में सुरक्षा बलों ने एक प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया है।

इसके आंकड़ों को विरोधी भी नकार नहीं सकते। मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा की जितनी भी चुनौतियां है इन सभी को न केवल एड्रेस किया गया है, बल्कि इसका परिणाम लाने का काम भी किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर से लेकर चंडीगढ़ और हरियाणा तक नारकोटिक्स से पूरी जनता परेशान है। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि जो मोदी सरकार ने अभियान चलाया है, 2021 में 75 साल में रिकॉर्ड नारकोटिक्स और इनके रैकेट चलाने वालो को पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दो-तीन सालों में नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ लड़ाई हम चरम सीमा पर ले जाएंगे और किसी को इजाजत नहीं होगी हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की और आने वाली नस्लों को नशे के गर्त में डुबाने की किसी को इजाजत नहीं होगी, यह नरेंद्र मोदी सरकार का एक दृढ़ निश्चय है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस कल्याण के बारे में, चाहे कोई भी सशस्त्र बल हो या संघ प्रदेश के सारे पुलिस बलों के कल्याण के बारे में बात हो, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ पुलिस कल्याण को गृह विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया है। उन्होंने कहा कि यह साल हमारा आजादी का 75वां साल है। आप जब पैदा हुए हैं तब आजादी का माहौल भी नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को इतिहास को पढ़ना चाहिए और इसीलिए आजादी के संघर्ष से युवा पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए मोदी जी ने तय किया है कि यह वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

हमारे देश भर के युवाओं को आजादी प्राप्त करने के लिए जो कड़ा संघर्ष हमारे पुरखों ने किया है उनसे परिचय कराया जाए। आजादी ऐसे ही नहीं मिली, नामी- अनामी कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, कई लोग अपने ओजस्वी कैरियर को समाप्त कर आजादी के आंदोलन की लड़ाई के अंदर कूद पड़े और कई लोगों ने अनेक प्रकार के जनजागृति के काम कर कर देश को आजाद कराने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और तब जाकर यह देश अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर आया। आज जो युवा स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार के अधिकारों के लिए सोच रहा है, हम इसलिए सोच रहे हैं कि हम आजाद भारत के अंदर सांस ले रहे हैं। हमारे संविधान ने आपको यह अधिकार दिया हैं। परंतु यह अधिकार आपको मिला है, इसके लिए कितनी कड़ी मशक्कत, कड़ा संघर्ष, बड़ा त्याग और बलिदान करना पड़ा है, वह हम सबको जरूर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें आजादी के लिए लड़ने का मौका ईश्वर ने नहीं दिया, क्योंकि हम सबका जन्म ही आजादी के बाद हुआ है। देश के लिए मरने का मौका भले ना मिला हो, देश के लिए जीने का मौका ईश्वर ने हमें दिया है और वह आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हर एक युवा तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके साथ-साथ मोदी जी ने हर क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव में इसे संकल्प वर्ष का नाम दिया है। हर क्षेत्र अपने संकल्प तय करेगा, हर व्यक्ति अपने संकल्प तय करेगा और देश की आज़ादी की जब शताब्दी बनाई जा रही होगी, तो करोड़ों संकल्पों का यह संपुट देश को महान बनाकर दुनिया के अंदर गौरवपूर्ण स्थिति में स्थापित करेगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि कई लोग मुझे कहते हैं कि हम व्यक्ति के नाते क्या कर सकते हैं, नागरिक के नाते क्या कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि 130 करोड़ लोग अगर संकल्प लेते हैं तो 130 करोड़ संकल्पों का यह संपुट हमारे देश को कितना आगे ले जा सकता है। यह कल्पना लेकर यह संकल्प के वर्ष में हमें संकल्प लेकर देश के लिए जीने की शुरुआत करनी चाहिए। इसी तरह से हर प्रशासनिक इकाई, छोटी सी नगरपालिका हो, या मुनीसिपल कॉरपोरेशन हो या चंडीगढ़ प्रशासन हो हर क्षेत्र के अंदर अपने लक्ष्य तय करने चाहिए। 25 साल में हम कहां होंगे। अगर यह लक्ष्य तय कर लेते हैं तो जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब यह सभी इकाइयां जब संकल्प सिद्धि करेगी तो यह आजादी का अमृत काल है 75 से 100 साल का, यह हमारे लिए परिश्रम की पराकाष्ठा का एक समय होना चाहिए। हम सब भारतीयों का परिश्रम भारत माता को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर बैठाए, इस प्रकार के भारत की कल्पना हमें करनी चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि मैं चंडीगढ़ प्रशासन को कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा 25 साल का एक संकल्प बनाया जाए। 5-5 साल की कार्य योजना बनाई जाए और इसके सालाना रिव्यू की एक योजना बनाई जाए तो 100 साल के बाद जब देश की शताब्दी के समय, लोगों को एक उन्नत मस्तक के साथ विश्व में खड़ा रहने का मौका मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कानून और व्यवस्था को सुधारने की इस प्रक्रिया से जुड़े हैं वह सभी लोग एक संकल्प लेकर अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे समाज में, हमारे देश में एक नई ऊंचाई प्राप्त हो इसके लिए प्रयासरत बनेंगे।

बीआरओ पर्यटन पोर्टल का उद्घाटन

विशेष संवाददाता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पर्यटन पोर्टल (https://marvels.bro.gov.in) का उद्घाटन किया। यूजर के अनुकूल इस वेबसाइट का उद्देश्य बीआरओ द्वारा निर्मित्त सड़क अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निर्देशित पर्यटन की ई-बुकिंग की सुविधा प्रदान करना है। आरंभिक चरण में, पोर्टल के माध्यम से अटल सुरंग, रोहतांग के निर्देशित पर्यटन के लिए केवल ई-बुकिंग की उपलब्ध होगी। शीघ्र ही, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में अवसंरचना परियोजनाओं को निर्देशित पर्यटन में शामिल कर लिया जाएगा। उमलिंग ला दर्रा में विश्व की सबसे ऊंची मोटर चलाने योग्य सड़क, अत्याधुनिक सेला बाई-लेन सुरंग तथा नेचिफु सुरंग उन परियोजनाओं में शामिल हैं जिन्हें इसमें सम्मिलित किया जाएगा।

इस अवसर पर सीमा सड़क के महानिदेशक (डीजीबीआर) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी द्वारा वेबसाइट से पहला टिकट रक्षा मंत्री को प्रस्तुत किया गया। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में पोर्टल के विकास में बीआरओ के प्रयासों की सराहना की तथा विश्वास जताया कि यह वेबसाइट दूर दराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने में दीर्घकालिक रूप से सहायक होगा। इस वेबसाइट में बीआरओ, सीमावर्ती राज्यों में इसके द्वारा निष्पादित कार्यो की प्रकृत तथा सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त पर्यटन गंतव्यों तथा स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के चित्र तथा वीडियो गैलरी शामिल हैं।

इसमें सिविल इंजीनियरिंग के क्षत्र में काम करने वालों, विशेष रूप से छात्रों तथा शिक्षाविदों के लिए निर्माण से संबंधित तकनीकी सूचना भी प्रदान की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में यह बीआरओ द्वारा निष्पादित

परियोजनाओं के इतिहास तथा महत्व के बारे में सूचना का सबसे सुगम तथा भरोसेमंद स्रोत बन जाएगा तथा आगामी परियोजनाओं के बारे में भी झलक उपलब्ध कराएगा।

रक्षा मंत्री ने इन क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अतुलनीय भूमिका निभाने के लिए बीआरओ की सराहना की और कहा कि अटल सुरंग के निर्माण के बाद उस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या छह गुनी बढ़ गई। उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में 75 स्थानों पर बीआरओ कैफे की स्थापना के बारे में विशेष उल्लेख किया और विश्वास व्यक्त किया कि ये कैफे यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे, दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देंगे तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे।

पर्यटन और यात्रा उद्योग विश्व में सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं तथा संपत्ति सुजनकर्ताओं में से एक हैं और सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये हैं। "अतुल्य भारत", 'एक विरासत को अपनाएं- अपनी धरोहर, अपनी पहचान', 'स्वदेश दर्शन' 'पूर्वोत्तर से प्यार के साथ', 'देखो अपना देश' तथा 'उड़ान' कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी, पर्यटन गंतव्य विकसित होंगे तथा रोजगार अवसरों का सृजन होगा।"

श्री राजनाथ सिंह ने पिछले छह दशकों के दौरान 60,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों, 850 प्रमुख पुलों, 19 एयरस्ट्रिप्स तथा चार सुरंगों के निर्माण और इस प्रकार सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के जरिये राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए भी सराहना की। उन्होंने राष्ट्र के विकास में कनेक्टिविटी तथा बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया तथा कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें, सेतु तथा सुरंगे सशस्त्र बलों की आवश्यकता की पूर्ति करने के अतिरिक्त क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, "पहले, सीमावर्ती क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास कभी भी प्राथमिकता नहीं रही और यह डर रहा कि कठिन समय में हमारे विरोधी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। हमने पूरी तरह इस दृष्टिकोण को बदल दिया है। किसी भी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का विकास राष्ट्र के विकास तथा वैश्विक स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। बदलते समय में, सभी क्षेत्र विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं।

हम सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। बीआरओ के पूंजीगत बजट में रिकॉर्ड बढोतरी की हाल की घोषणा फिर से इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।"

रक्षा मंत्री ने इस तथ्य की सराहना की कि दूर दराज के क्षेत्र अब प्रवासी लोग वापस अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। जिन लोगों ने पहले रोजगार, शिक्षा तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में अपने गावों को छोड़ दिया था, अब इन क्षेत्रों में विकास होता देख वापस लौटने लगे हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के हुरी गावं की चर्चा की, जिसके निवासी बीआरओ द्वारा जिला मुख्यालय से संपर्क सुनिश्चित किए जाने के बाद वापस लौट आए।

उन्होंने कहा, "अटल सुरंग तथा उमलिंग ला दर्रा बीआरओ की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं जिन्होंने भारत को विश्व के मानचित्र पर ला खड़ा किया है। बीआरओ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्म निर्भर भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।"

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि पर्यटन और यात्रा उद्योग विश्व में सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं तथा संपत्ति सुजनकर्ताओं में से एक हैं और सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये हैं। "अतुल्य भारत", 'एक विरासत को अपनाएं- अपनी धरोहर, अपनी पहचान', 'स्वदेश दर्शन' 'पूर्वोत्तर से प्यार के साथ', 'देखो अपना देश' तथा 'उड़ान' कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य देश का सर्वागीण विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी, पर्यटन गंतव्य विकसित होंगे तथा रोजगार अवसरों का सृजन होगा।"

रक्षा से संबंधित विषयों के साथ विशेष रूप से युवाओं के जुड़ने की इच्छा की ओर इंगित करते हुए, राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से रक्षा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानों की सुरक्षा तथा मर्यादा का ध्यान रखते हुए उद्योग, स्टार्ट अप्स तथा पूर्व सैनिकों की सहायता से लोगों के लिए ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों, युद्ध स्मारकों, प्रशिक्षण अकादमियों या अन्य समान प्रकार के रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा आयोजित करने की संभावना की खोज करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा होगी तथा साथ ही साथ राजस्व भी सृजित होगा।

डीजीबीआर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह वेबसाइट लोगों को आसानी से उन स्थानों की यात्रा करने में सक्षम बनाएगी जो पर्यटकों तथा शिक्षाविदों के बीच लोकप्रिय हो गए हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) संजीव मित्तल तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बीआरओ कर्मी तथा पर्यटन एवं यात्रा एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से भाग लिया।

दलबदलुओं को जनता ने अच्छा सबक सिखाया

विशेष संवाददाता

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ऐन पहले दलबदल करने वाले ज्यादातर विधायकों का दांव खाली गया और ऐसे 80 प्रतिशत जनप्रतिनिधि सियासी संग्राम में सफलता हासिल नहीं कर सके। दलबदल कर विभिन्न राजनीतिक दलों का हाथ थामने वाले इन 21 विधायकों में से सिर्फ चार को ही जीत नसीब हुई है। हम आपको बता दें कि पाला बदलने वाले इन विधायकों में से 9 भाजपा जबकि 10 सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। जिन प्रमुख नेताओं को हार का सामना करना पड़ा उनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य व धर्म सिंह सैनी के अलावा बरेली की पूर्व महापौर सुप्रिया ऐरन शामिल हैं। ये नेता चुनाव से ऐन पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे।

उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार में करीब पांच वर्ष तक मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने ऐन चुनाव के मौके पर भाजपा पर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में पिछड़ों को एकजुट करने की मुहिम शुरू की थी लेकिन खुद ही चुनाव हार गये। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो दावा किया था कि वह भाजपा की चूलें हिला देंगे और उसे नेस्तनाबूत कर देंगे लेकिन उनकी खुद की

उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार में करीब पांच वर्ष तक मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने ऐन चुनाव के मौके पर भाजपा पर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

चूलें ऐसी हिल गयी हैं कि लंबे समय तक अब राजनीतिक रूप से वापस खड़े नहीं हो पाएंगे। अखिलेश यादव के समक्ष भी अब स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक हैसियत का खुलासा हो गया है इसीलिए अब वह भी उन्हें शायद पहले की तरह तवज्जो नहीं दें।

उत्तर प्रदेश की ही तरह यदि उत्तराखण्ड की ओर देखें तो वहां भी भाजपा को मटियामेट कर देने के दावे करने वाले यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत खुद ही राजनीतिक रूप से मटियामेट हो गये। उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के चलते कहीं के नहीं रहे। ऐन चुनावों

से पहले वह अपने बेटे और भाजपा विधायक संजीव आर्य के साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गये। कांग्रेस ने दोनों विधायक पिता-पुत्र को टिकट भी दे दिया लेकिन बाजपुर विधानसभा सीट से यशपाल आर्य बस हारते-हारते बचे और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल से चुनाव हार गये। अब यशपाल आर्य के पास विपक्ष में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं हरक सिंह रावत की बात करें तो वह भी भाजपा को चुनौती देते हुए चुनावों से पहले पार्टी छोड़ गये थे। हरक सिंह रावत खुद तो चुनाव नहीं लड़े थे लेकिन अपनी पुत्रवधू अनुकृति को कांग्रेस के टिकट पर लैंसडाउन से चुनाव लड़वाया। मगर मोदी लहर को वह भांप नहीं सके और लैंसडाउन से भाजपा जीत गयी। इस तरह हरक सिंह रावत भी अब घर बैठ गये हैं और भाजपा को भी रोजाना रूठने वाले नेताओं से छुटकारा मिल गया है। वहीं ऐन चुनावों के समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आये किशोर उपाध्याय और सरिता आर्य विधानसभा चुनाव जीत कर विधायक बन गये। किशोर उपाध्याय को तो नयी भाजपा सरकार में मंत्री बनाये जाने के भी आसार हैं।

दलबदलुओं के बारे में बात करते हुए यदि आपको वापस उत्तर प्रदेश ले चलें तो आंकड़े बताते हैं कि अदिति सिंह (रायबरेली), अनिल कुमार सिंह (पुरवा) और मनीष कुमार (पड़रौना) ने दलबदल के बाद भाजपा के टिकट पर चुनाव में जीत हासिल की। जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने चुनाव से ठीक पहले सपा का हाथ थामा व घोसी सीट से विजयी रहे। हम आपको याद दिला दें कि अदिति सिंह ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया था।

दलबदल के बाद जिन विधायकों ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत नहीं सके उनमें राकेश सिंह (हरचंदपुर), नरेश सैनी (बेहट) वंदना सिंह (सगड़ी), रामवीर उपाध्याय (सादाबाद), सुभाष पासी (सैदपुर) और हरिओम यादव (सिरसागंज) शामिल हैं। पाला बदलकर सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत से वंचित रहे विधायकों में ब्रजेश प्रजापति (तिंदवारी) रौशन लाल वर्मा (तिहर), भगवती सागर (घाटमपुर), दिग्विजय नारायण (खलीलाबाद), माधुरी वर्मा (नानपारा) और विनय शंकर त्रिपाठी (चिल्लूपार) शामिल हैं।

वहीं, रामपुर की स्वार सीट पर कांग्रेस का टिकट ठुकराकर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में अपना दल (एस) से चुनाव मैदान में उतरे नवाब परिवार के हैदर अली खान को सपा उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम खान ने 61 हजार मतों से हराया। बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र में 2017 में भाजपा से चुनाव जीते सुरेंद्र सिंह इस बार टिकट नहीं मिलने पर विद्रोह कर विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें तीसरे नंबर पर धकेल दिया। अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले सुरेंद्र सिंह को 28,615 मत मिले। तो इस प्रकार दलबदलुओं पर से जनता का विश्वास उठता दिख रहा है। जनता सिर्फ विकास की राजनीति को तरजीह देती है। नेताओं की अवसरवादिता को अब वह और सहने के मूड में नहीं है।

देश के चौमुखी विकास के लिए मोदी सरकार अग्रसर होकर कार्य कर रही : गोपाल जी ठाकुर

निम्मी ठाकुर

दरभंगा लोकसभा क्षेत्र मे विकास के लिए समर्पित नाम से पहचान रखने वाले गोपाल जी ठाकुर ने औपचारिक भेंट वार्ता के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश सहित चार अन्य राज्यों में हुये, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चार राज्यों में प्रचंड विजय मिली है, इस पर उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास के साथ-साथ ही इन प्रदेशों मे कई ऐसे विकास कार्य व विकास योजनाएं प्रदेशों में चल रही है उसका नतीजा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मणिपुर गोवा में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उन्होंने साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी ने जो जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है उससे आने वाले2024के लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। आगे उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री के चेहरे पर पूरा भरोसा करती है प्रधानमंत्री के कार्य करने की दूरदर्शी नजर पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है ।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बड़े ही सरल ढंग से देश के विकास के लिए काम करते है ।

इस मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि उनकी लोकसभा क्षेत्र के साथ बिहार में किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं उसमें एम्स, एयरपोर्ट, आईटी पार्क, ओ सी रेल महासेतु, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, समस्तीपुर दरभंगा रेलवे का दोहरीकरण और विद्युतीकरण, कक्कड़ घाटी शीशों बाईपास रेल निर्माण सकड़ हसनपुर रेल लाइन का विस्तार पूसा विद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा देना राजेंद्र पुल के बगल में गंगा नदी पर पुल का निर्माण बरौनी थर्मल पावर को चालू करना, अयोध्या से जनकपुर चार लेन सड़क का निर्माण (राम जानकी पथ) आमस दरभंगा सिक्स लेन का निर्माण बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे कचरा निस्तारण प्लांट हेतु राशि देना, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, दरभंगा शहर केअंदर ग्राउंड गैस पाइपलाइन मिथिला के पाग पर डाक टिकट जारी करना, मैथिली को सीबीएससी कोर्स में शामिल करना ऐसे अनेक कार्य मिथिला में हुए हैं और होने हैं,उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समस्त मिथिला वासियों की तरफ से होली के शुभ अवसर पर बधाई राज्य के एनडीए और केंद्र के एनडीए के सरकार को भी बधाई दी।

दरभंगा से लोकसभा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आने वाले जुड़ शीतल कि मिथिला वासी व देश के सभी लोगों को मिथिला नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई विरासत को आगे संजोए रखने के साथ-साथ अपने आने वाली पीढ़ी को हम सबको अपनी परंपराओं से अवगत कराते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी मिथिला परंपरा और हमारी मिथिला बोली मिथिला के पारंपरिक त्योहार जन जन तक पहुंच सके । उन्होंने कहा कि जुड़ शीतल नव वर्ष का स्वागत मिथिला में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है ,साथ ही इस दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए पुराने पौधों को जल दिया जाता है, और वृक्षारोपण किया जाता है।जिससे कि प्रदूषण ना फैले।

उन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी परंपराएं त्यौहार हैं वह कहीं ना कहीं हम लोगों को संदेश के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण भूमि संरक्षण आदि की के संदेश देते है ।उन्होंने पत्रिका की संपादक निम्मी ठाकुर को बताया कि जुड़ शीतल की मिथिला में काफी महत्ता रही है। यह पर्व मिथिला की प्रकृति से जुड़े संस्कृति का भी प्रतीक है। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में तो इस पर्व की प्रासंगिकता व महत्व और भी अधिक बढ़ गयी है। जानकारी के अभाव और आधुनिक भौतिकवादी संस्कृति के बढ़ते प्रचलन व चिताजनक है। मिथिला की वर्तमान पीढ़ी के कई लोग से आज भी इस पर्व का वजूद कायम है।

अपने मूल जड़ों व लोक संस्कृति से जुड़ा समाज, प्रदेश व देश प्रगति की ओर बढ़ता है - जितेंद्र नारायण झा

निम्मी ठाकुर

भारत देश के अनेक राज्य भिन्न-भिन्न बोली भाषा रंगों से बिखरी हुई है बिहार राज्य देश के कोने कोने में यहां के लोग अपनी लोक संस्कृति अपनी बोली भाषा को संजोए हुए प्रदेश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं दिल्ली में रह रहे बिहार राज्य के लोग अपनी संस्कृति और बोली के प्रति भी सजग होकर कार्य करते दिखते हैं।

आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रही हैं ,पॉलिटिकल ट्रस्ट की संपादक निम्मी ठाकुर।

चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ मुस्कुराहट लिए अपनी बोली मिथिला में बात करने को अपना गौरव महसूस करने वाले दिल्ली पुलिस के एसीपी जितेंद्र नारायण झा से बातचीत की कुछ अंश।

उन्होंने इस मौके पर विशेषकर मैथिली बोली भाषा को अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हर जागरूक और सक्षम मिथिला वासी से अपील की और कहा कि हम सबको अपने मूल गांव से जुड़ा रहना चाहिए जिससे कि गांव के साथ-साथ प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने इस अवसर पर पत्रिका के संपादक निम्मी ठाकुर से बताया कि मिथिला समाज के लोगों को अपने समाज को आगे लाने के लिए अपनी बोली भाषा संस्कृति लोग विधाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास और बीड़ा उठाना चाहिए उन्हें इस अवसर पर कहा कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गांव में जाकर अपने क्षेत्र के विकास और बोली भाषा लोक संस्कृति के लिए काम करूंगा साथ ही उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के विकास में हर नागरिक को अपना जवाबदेही तय करनी चाहिए जिससे समाज के साथ-साथ प्रदेश और देश को नई गति और नया आयाम मिलेगा और आने वाले युवाओं को अपने समाज के लोग संस्कृत से जुड़ा रहने के साथ-साथ मानव प्रेम भी बरकरार रहेगा ।

ज्ञात हो दिल्ली पुलिस के एसीपी जितेंद्र नारायण झा को पिछले दिनों राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया उनके द्वारा दिल्ली पुलिस में किए गए उत्कृष्ट कार्यो के लिए सम्मान उनको दिया गया जिससे कि पूरे बिहार समाज के लोगों में खुशी देखने को मिला। श्री झा ने बताया कि वह समय मिलने पर कुछ कविताएं भी लिखते हैं जो समाज वातावरण में उनको देखने को मिलता है उसी पर वह कुछ पंक्तियां लिख कर समाज की पीड़ा और समाज की सुंदरता और देश की खूबसूरती को अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास करते हैं।

लेखक जितेंद्र नारायण झा एसीपी दिल्ली पुलिस

कंस्टीटूशन क्लब में स्वर्गीय ललित मोहन मिश्रा का 99वॉं जन्म दिवस मना कर उनको याद किया गया

स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्रा जी पूर्व रेलवे मंत्री विदेश व्यापार मंत्री राज्य सुरक्षा मंत्री उप विदेश मंत्री और उप गृह मंत्रालय मंत्री रहे। इस अवसर पर स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र जी के शहीद स्मारक इंडिया में इंडिया मूविंग फॉरवार्ड इस विषय पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम पद्मभूषण विजेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार गुलाम नबी आजाद मौजूद रहे।

उनके जन्म दिवस के अवसर पर मुख्य वक्ताओं में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक तनखा पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज शिवाकृति सिंह आदि समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे ,एसोसिएशन के श्री प्रदीप राय, उनके जन्म दिवस के अवसर पर लक्ष्मी नगर से विधायक व भारतीय जनता दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अभय वर्मा ने कहा की ललित नारायण मिश्रा जी ललित बाबू के नाम से भी जाने जाते थे, उनका जन्म 1923 मैं बसंत पंचमी के दिन बसंतपत्ति में बिहार के सहरसा जिले में हुआ था। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन में की गई मेहनत और राजनीति के माध्यम से प्रदेश का विकास देश का विकास उसको सबको अपने जीवन में अपना कर समाज और देश व प्रदेश का विकास करना चाहिए।

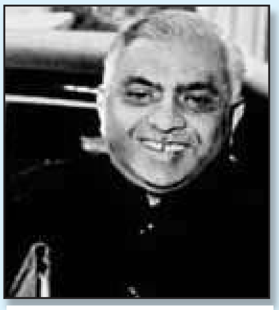

स्वःललित नारायण मिश्रा जी का जन्मदिवस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली 23 मार्च को 2022 को मनाया गया।

इस कार्यक्रम के अधिक जानकारी पत्रिका के संपादक निम्मी ठाकुर को ऑल इंडिया मानव समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष हीरालाल प्रधान देते हुए कहा कि स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्रा का जन्मदिवस दिल्ली के कंस्टीटूशन क्लब में मनाया गया और उनके जीवनी पर इस मौके पर कई वक्ताओं ने प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि ललित नारायण मिश्र जी बिहार मे विकास पुरुष नाम से जाने जाते थे।

आईआईटी से नियोक्ता और उद्यमी निकलेंगे, कर्मचारी नहीं

विशेष संवाददाता

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे परिसर में छात्रों के लिए एक नए आवास – छात्रावास 17 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने छात्रावास में पट्टिका का अनावरण भी किया और छात्रावास परिसर में एक पौधा लगाया। छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम और संकाय के अलावा, छात्रों को अच्छा अनुभव करने के लिए परिसर का माहौल महत्वपूर्ण है। यह माहौल सकारात्मकता पैदा करता है, जो छात्र जीवन का 50 प्रतिशत है। यदि आप सकारात्मक हैं, तो आप सहज रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति में नवप्रवर्तन और योगदान करने की क्षमता होती है। आज हम लोगों ने आईआईटी बॉम्बे जैसे इस महान संस्थान और परिसर में एक नया अध्याय जोड़ा है।

नए छात्रावास में 1,115 कमरे हैं और इमारतों के पहले समूह में से एक है जिसे आईआईटी बॉम्बे ने पूरी तरह से उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) से प्राप्त धन से बनाया है। इसकी अनुमानित लागत 117 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आईआईटी से नियोक्ता और उद्यमी निकलेंगे, कर्मचारी नहीं। आईआईटी बॉम्बे के कौशल में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि संस्थान की प्रतिभाशाली मानव पूंजी रोजगार सृजनकर्ता के रूप में उभरेगी, वैश्विक कल्याण के लिए नवाचार और काम करेगी, और एक मजबूत तथा आत्म-निर्भर भारत के निर्माण की दिशा में भी काम करेगी।

आईआईटी के पूर्व छात्रों के योगदान की सराहना करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस योगदान का बेहतर तरीके से दस्तावेजीकरण करने और इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छह पुराने आईआईटी ने मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था में 300 से 400 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जो आईआईटी बॉम्बे के माहौल से निकलकर बाहर

आता है, वह कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। हमारे पूर्व छात्र वे हैं जो विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं। हमें अपने योगदान का बेहतर तरीके से दस्तावेजीकरण करने और अपनी क्षमता को बढ़ावा देने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के पक्ष पर विचार करते हुए क्षमता की फिर से ब्रांडिंग करने की आवश्यकता है, इसमें यह भी देखना है कि प्रौद्योगिकी आईआईटी बॉम्बे की विशेषता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तेजी से बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और महामारी से प्रेरित वैश्विक चुनौतियों के इस युग में हमारे लिए ढेर सारे अवसर हैं।

उन्होंने कहा कि "आज हम कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। महामारी और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे हमें निपटने की आवश्यकता है। हमने 2020 से शुरू होने वाले तीन वर्षों में महामारी की तीन लहरें देखी हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उम्मीद जताई की कि आईआईटी बॉम्बे यह सुनिश्चित करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा कि भारत को नई विश्व व्यवस्था में अपना सही स्थान मिले।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान का युग होने जा रही है और उन्होंने इसमें प्रमुख भूमिका निभाने के लिए आईआईटी बॉम्बे का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि "मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश में कुछ ही प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं जिनके पास 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान है और आईआईटी बॉम्बे उनमें से एक है।" केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है और भारत ने दिखाया है कि उसके पास जटिल वैश्विक समस्याओं का समाधान है। उन्होंने सुझाव दिया कि आईआईटी को आपदा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा और स्थायित्व के क्षेत्रों को शामिल करते हुए अगले 50 वर्षों के लिए भारत की जरूरतों का खाका तैयार करना चाहिए और उन जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम पर लग जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने आईआईटी बॉम्बे समुदाय को आने वाले दशकों में राष्ट्र की कार्य प्रणाली को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि "जब हम 5-10 वर्षों के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें विश्वास के साथ यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे ने 21वीं सदी को अपने पाले में ले लिया है और इतिहास को आकार देने में योगदान दिया है।" आईआईटी बॉम्बे के निदेशक प्रो. सुभासिस चौधरी ने मंत्री के समक्ष संस्थान और वर्षों में इसके विकास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।

अपने संबोधन में प्रो. सुभासिस चौधरी ने कहा कि, आईआईटी प्रणाली भारत सरकार के संरक्षण में फली-फूली और हमारे पूर्व छात्रों ने अपने चुने गए करियर के सभी रूपों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुझे विश्वास है कि यह अत्याधुनिक छात्रावास परिसर में छात्रों के लिए माहौल को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईआईटी बॉम्बे के अध्यक्ष डॉ. पवन गोयनका ने संस्थान के बुनियादी ढांचे के सुधार में सहयोग और समर्थन के लिए सरकार को धन्यवाद दिया।

धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान लाँच

विशेष संवाददाता

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल विश्व जल दिवस- 2022 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के पेय जल तथा स्वच्छता विभाग द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम में धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च किया। नौ मंत्रालयों- जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा कार्य तथा खेल मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय- ने एक संयुक्त परामर्श पर हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत कार्यक्रम क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों के साथ तालमेल के आधार पर धूसर जल प्रबंधन अपने-अपने स्तर पर प्रारंभ करेंगे।

सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष का विषय है 'भू-जलः अदृश्य को दृश्यमान बनाना'। उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल महत्वपूर्ण बल्कि समय पर प्रारंभ किया गया अभियान है। उन्होंने कहा कि हम भले ही भू-जल को देखने में सक्षम नहीं हैं लेकिन इसका प्रभाव हर जगह दिखता है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहलू पर फोकस करने के लिए उनके मंत्रालय ने जल-भागीदारी के माध्यम से धूसर जल प्रबंधन के उद्देश्य से सुजलाम 2.0 प्रारंभ कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत हमारी योजना समुदायों, पंचायतों, स्कूलों, आंगनवाड़ी जैसे संस्थानों को संगठित करना है ताकि धूसर जल प्रबंधन कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि धूसर जल का बेहतर प्रबंधन उसी स्थान पर किया जा सकता है जहां से यह उत्पन्न होता है और यदि यह एकत्रित होता है और रुका रहता है तो इसे बड़े प्रबंधन और अवसंरचना चुनौती में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पीआरआई घर और सामुदायिक सूखने वाले गड्ढे बना कर सर्वाधिक उचित स्तर पर धूसर जल प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा, धूसर जल प्रबंधन के काम को लागू करने के लिए धन एसबीएम-जी फेस चरण-2 या 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान या एमजीएनआरईजीएस या सभी के मेलजोल के माध्यम से जुटाया जाएगा। इस अभियान में लोग सामूहिक रूप से स्थिति का आकलन करेंगे, योजना बनाएंगे और धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों को लागू करेंगे। धूसर जल प्रबंधन के महत्व को लोकप्रिय बनाने के लिए आईईसी के प्रयास तथा राज्य जिला और स्थानीय स्तर पर सामूहिक सामुदायिक कार्य राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर शुरू किया जाएगा। मैं अपने सभी पीआरआई तथा वीडब्ल्यूएससी सदस्यों, स्वच्छाग्राहियों, स्वयं सहायता समूह के नेताओं से स्थानीय स्तर पर सुजलाम 2.0 अभियान तेजी से चलाने का आग्रह करता हूं। यूनिसेफ के जल तथा स्वच्छता प्रमुख निकोलास ऑसबर्ट ने अपने स्वागत भाषण में धूसर जल प्रबंधन पर वैश्विक परिदृश्य को साझा किया। उन्होंने कहा, पूरे विश्व में 2.2 बिलियन लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करना है। आज भारत सरकार के अनेक मंत्रालय जल स्रोत को स्थायी बनाने में रोडमैप तैयार करने के लिए एक साथ आए हैं, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। सरकार ने धूसर जल प्रबंधन पर ध्यान दिया है। अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिदिन 31 बिलियन लीटर धूसर जल निकलता है। जल संरक्षण के लिए स्थायी व्यवहारों को विकसित करने की आवश्यकता है।

पेयजल तथा स्वच्छता विभाग की

सचिव श्रीमती विनी महाजन ने भारतीय संदर्भ के बारे में कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमें नौ मंत्रालयों का समर्थन मिला है क्योंकि बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन के साथ प्रत्येक व्यक्ति जल के महत्व और उस पर दबाव को महसूस करता है। अगस्त, 2019 में जल मिशन लॉन्च किए जाने के बाद से इसके अंतर्गत 6 करोड़ नल से पानी के क्रेक्शन दिए गए हैं। देश में कुल 9.24 करोड़ परिवारों को नल से जल मिल रहा है। वर्तमान संदर्भ में ग्रामीण परिवारों से काफी जल निकासी होगी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सुजलाम 2.0 अभियान के अंतर्गत 6 लाख गावों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर गतिविधि तेज होगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत बड़ी संख्या में गांव 100 प्रतिशत परिपूर्ण हो गए हैं। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से पानी का क्रेक्शन देना है, अब गांव में निकले धूसर जल के प्रबंधन पर फोकस करने का समय आ गया है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन विभाग के सचिव पंकज कुमार ने कहा कि भू-जल जलाशय के रूप में काम करता है जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। लेकिन इसे नियमित अंतराल पर भरने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान जल संकट का सामना कर रहे जिलों को कवर करने के लिए 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे प्रधानमंत्री द्वारा 2021 में सभी ग्रामीण तथा शहरी जिलों तक ले जाया गया। 2022 में जल शक्ति अभियान 29 मार्च, 2022 को लॉन्च किया जाएगा।

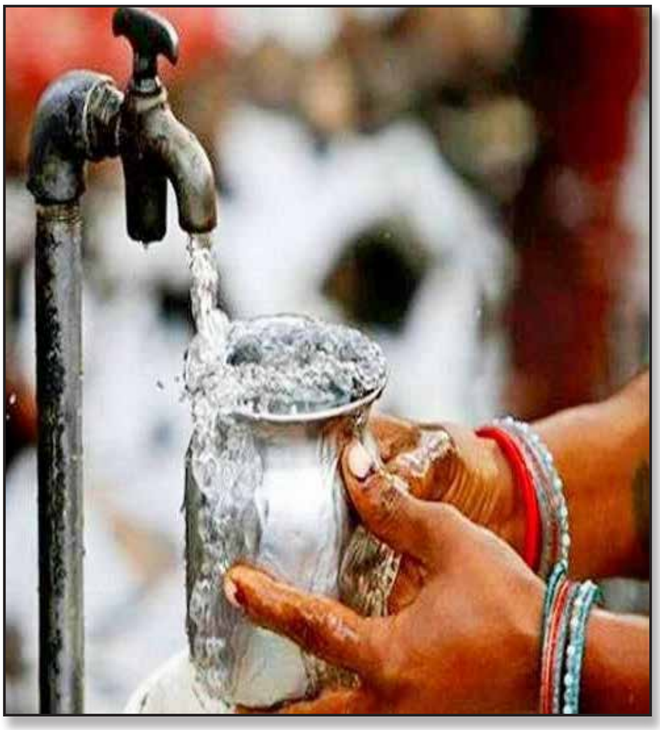

उन्होंने बताया कि विभाग के अंतर्गत एक दूसरा कार्यक्रम अटल भू-जल योजना है जिसे सात राज्यों के चुनिंदा क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, जिसमें लोग अपनी जल सुरक्षा योजना तैयार करते हैं, इस योजना में इस बात का ब्यौरा होता है कि लोग किस तरह जल प्राप्त कर रहे हैं, जल की खपत कितनी मात्रा में हो रही है, जल संरक्षण के तरीकों को अपनाया जाता है और किस तरह जल के इस्तेमाल को सामान्य बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण घरों से निकलने वाले धूसर जल का उचित प्रबंधन करना होगा अन्यथा इससे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेन्द्र नाथ सिन्हा ने कहा कि अभियान लागू करते समय पहले के कार्यक्रमों से सीख लेना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के जनजातीय जिला नंदुरबार में की गई पहल की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि वहां बड़ी संख्या में गड्ढे खोदे गए थे, जिससे वहां के लोग मलेरिया, डेंगू तथा अन्य जल और मच्छरजनित बीमारी की घटनाओं को कम करने सक्षम हुए। इसके अलावा पर्यावरण और पारिस्थितिकीय लाभ मिला। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बारे में संवेदी बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि नल से जल उपलब्ध होने के बाद बड़े पैमाने पर प्रत्येक घर से जल निकलेगा। हम स्वयं सहायता समूहों से समर्थन चाहते है क्योंकि ये समूह गांव में विकास से जुड़े सामाजिक विषयों से जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि गांव में उठाए गए विषयों को फिर से देखा जाएगा ताकि जल और स्वच्छता की चिंताओं को कवर किया जा सके। उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास आठ करोड़ से अधिक महिला सदस्यों का नेटवर्क है, जो अभियान को समर्थन देगा।

एमजीएनआरईजीएस अनुसूची 1 पैरा 4 के अंतर्गत गड्ढा बनाने, धूसर जल शोधन के लिए पोखरों को स्थिर बनाने और बड़े पैमाने पर जल निकासी से जुड़े कार्य शुरू किए गए हैं। 23 लाख से अधिक जल सोखने के गड्ढे, 48 लाख ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन ढाचे और एक लाख आंगनवाड़ी केन्द्र शौचालय के साथ बनाए गए हैं। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। एमजीएनआरईजीएस मांग प्रेरित कार्यक्रम है और यदि समुदाय को संवेदी बनाया जाता है तो जल और स्वच्छता से संबंधित कार्य गांव में ही शुरू किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदीवर पांडे ने कहा कि देश में 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जो पोषाहार और प्रारंभिक बाल देखभाल का काम करते है। इन केन्द्रों में 0-6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक भोजन मिलता है। इसमें से 12.23 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वच्छ पेयजल प्रदान किया गया है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा जल जीवन मिशन के अंतर्गत है। इसी तरह 11.02 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता की सुविधाएं हैं और इसके प्रमुख कार्य स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत किया गया है। इसने शिशु और मातृ मृत्यु दर कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में 4.68 लाख किचन गार्डन हैं। साफ किए गए धूसर जल का इस्तेमाल इन किचन गार्डन को

पानी देने में किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण गतिविधियों की दिशा में व्यवहार परिवर्तन लाने में परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में देश के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) तथा राष्ट्रीय युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के कार्यकर्ताओं ने जल संरक्षण पर अतीत में 1.33 लाख गतिविधियां चलाई और समुदाय को संगठित करने के लिए 16.15 लाख गतिविधियां चलाई गई हैं। सुजलाम 1.0 को जन आंदोलन बनाने के लिए 61 लाख युवा नेताओं ने विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी की है।

इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री अनिल कुमार झा ने कहा कि 36,000 से अधिक जनजातीय गांव हैं जो आकांक्षी जिलों में आते हैं। उनके लिए पेयजल सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनका अस्तित्व कृषि तथा वन उत्पाद पर निर्भर है। अनेक आश्रमशालाएं और नवोदय विद्यालय हैं जो जनजातीय आबादी के लिए शिक्षा के केन्द्र हैं। जनजातीय आबादी अधिकतर अपनी जल आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक झरनों पर निर्भर रहती है। उन्होंने कहा कि हम इन झरनों का एक मानचित्र बना रहे हैं और जल संसाधनों को मजबूत बनाने में पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के प्रयासों की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि सुजलाम 2.0 अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग की सचिव अनिता करवाल ने कहा कि सुजलाम 2.0 अभियान के हिस्से के रूप में स्कूलों की न केवल धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका है बल्कि स्कूल जागरूकता सृजन और बच्चों तथा युवाओं के बीच व्यवहार परिवर्तन प्रोत्साहन के लिए केन्द्र हैं क्योंकि स्कूल स्थायी जल और स्वच्छता के लिए एम्बेस्डर के रूप में काम करते हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री राजेश भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों पर धूसर जल शोधन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), एमजीएनआरईजीएस तथा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत धन का इस्तेमाल किया जा सकता है और भू-जल को फिर से चार्ज करने के लिए साफ किए गए जल का फिर से उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल संचय ढांचे को नए स्वास्थ्य सेवा भवनों के अभिन्न भाग बनाया जाना चाहिए।

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव श्रीमती लीना नंदन ने कहा कि जल के अधिकतम उपयोग के लिए इसको फिर से चार्ज करने, पुनः उपयोग तथा रि-साईकिलिंग में हम समर्थन का आश्वासन देते हैं। यह समय कंधा से कंधा मिलाकर चलने का है और हम जल ढांचे को रि-चार्ज करने के प्रति अपना संकल्प दोहराते हैं।पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि 10,000 से अधिक ग्राम पंचायते जल के अभाव में हैं। अटल भू-जल योजना के अंतर्गत दो लाख ग्राम पंचायतों ने जल संरक्षण योजना विकसित की है जिसे ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) से जोड़े जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के प्रयासों में मंत्रालयों को शामिल होना चाहिए और जल संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देनी चाहिए। जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन के एएस तथा एमडी श्री अरूण बरोका ने कहा कि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने अपनी गतिविधियां सर्कुलर अर्थव्यवस्था में धूसर जल शोधन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका उजागर करने की ओर कर दी है। इसका आधार तीन आर- रिड्यूस (कम करना), रियूज (पुनः उपयोग) तथा रि-चार्ज है। उन्होंने कहा कि भू-जल न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि स्थायी जल आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि अब स्वच्छ भारत मिशन अपने क्रियान्वयन के दूसरे चरण में है जिसके अंतर्गत अब तक 48,376 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है जबकि 56,449 गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) से कवर किए गए हैं और 31,095 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि सुजलाम 1.0 अभियान के अंतर्गत 12,78,379 घर तथा सामुदायिक जल सोखने के गड्ढे बनाए गए हैं।

सुजलाम 2.0 अभियान के बारे में अरुण बरोका ने कहा कि एसबीएम (जी) चरण-1 के अंतर्गत हासिल उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए तथा ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करके गांवों में समग्र स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान का फोकस पंचायत घर, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं, स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों तथा अन्य सरकारी संस्थानों में संस्थागत स्तर पर धूसर जल परिसंपत्तियां बनाने पर है। सभी राज्यों और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से अगस्त, 2021 में प्रारंभ सुजलाम 1.0 अभियान के अंतर्गत में बड़ी सफलता प्राप्त की गई और पूरे देश में घरेलू तथा समुदायिक स्तर पर एक मिलियन पानी सोखने के गड्ढे बनाए गए हैं।

श्री बरोका ने बताया कि विभाग द्वारा धूसर जल प्रबंधन पर तकनीकी मैन्यूअल विकसित किए गए हैं जिससे धूसर प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को मदद मिलेगी। ये हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और राज्य तथा जिला प्रशासन को भी उपलब्ध कराए गए हैं। धूसर जल मूल रूप से वह जल है जो रसोई, स्नानघर और साफ-सफाई जैसे घरेलू कामों में उपयोग किया जाता है। धूसर जल गंदगीमुक्त होता है और इसमें शौचालयों से निकला काला जल शामिल नहीं होता। उन्होंने सभी से सुजलाम 2.0 अभियान में शामिल होने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी धूसर जल प्रबंधन लक्ष्य सुनिश्चित करने का आग्रह किया। अंत में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पटौरा, पंजाब के गुरदासपुर जिले के धियानपुर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के जलबपुर तथा मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों के पोम्लाहीर गांव के सरपंच के साथ बातचीत की गई। इन लोगों ने बताया कि किस तरह धूसर जल प्रबंधन से जीवन स्थिति में सुधार आया है और भू-जल स्तर को रि-चार्ज करने में मदद मिली है।

भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र मजबूत होकर उभर रहा

अनुष्का

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि सरकार उड्डयन क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ एक रचनात्मक सहयोगी होगी और देश में नागरिक उड्डयन के विकास के लिए उनके साथ काम करेगी। आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2022 का औपचारिक उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि, "हम वर्गाकार मेज में विश्वास नहीं करते हैं, हम इस क्षेत्र और समग्र रूप से अपने देश की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने मंत्रालय में गोलमेज सम्मेलन में विश्वास करते हैं।"

वाणिज्यिक, सामान्य और व्यावसायिक उड्डयन के लिए एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन 'इंडिया@75: न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री' थीम के साथ हो रहा है। कल शुरू हुए इस कार्यक्रम का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

उद्घाटन सत्र में जीन बैप्टिस्ट डीजेब्बारी, परिवहन राज्य मंत्री, पर्यावरणीय पारगमन मंत्री, फ्रांस; एनगमपासोंग मुओंगमनी, लोक निर्माण और परिवहन उप मंत्री, लाओस; प्रेम बहादुर अली, संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री, नेपाल; डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन, तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल; दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री; और नाकप नालो, नागरिक उड्डयन मंत्री, अरुणाचल प्रदेश शामिल हुए। उद्घाटन सत्र के दौरान मंच पर भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव राजीव बंसल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी, फिक्की नागरिक

उड्डयन समिति के अध्यक्ष और एयरबस समूह के अध्यक्ष और एमडी रेमी माइलर्ड मौजूद थे।

इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, विमानन क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों के सीईओ और अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया। उद्घाटन के इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र कोरोना महामारी की अवधि के दौरान बहुत सारे परीक्षणों और आपत्तियों से गुजरा है, लेकिन यह मजबूत, ज्यादा फिट होकर उभर रहा है और चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। इस क्षेत्र ने लचीलापन दिखाया है और अगले साल तक हम घरेलू यात्रियों की कोविड से पहले की संख्या को पार कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक दो दिनों में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से फिर से शुरू होने जा रही हैं, और भारत से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी।

श्री सिंधिया ने कहा कि विंग्स इंडिया 2022 एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष- आजादी का अमृत महोत्सव में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया गति शक्ति का एजेंडा, एक दोतरफा पहल और गति तथा शक्ति देने का ऐसा तालमेल है जो भारत को आने वाले वर्षों तक चलाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के विभिन्न विभाग भारत को शक्ति देने के लिए एक साथ आए हैं और, जैसे-जैसे भारत 75 से 100 वर्ष की ओर बढ़ेगा, यह नई शक्ति के रूप में उभरेगा क्योंकि प्रतिमान बदल गया है और बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का निर्माण केवल आर्थिक केंद्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश के सभी हिस्सों में सभी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में 3.1 का आर्थिक गुणक और 6.1 का रोजगार गुणक है। इसका मतलब है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक रुपये का निवेश लंबे समय में अर्थव्यवस्था में 3.1 रुपये जोड़ता है, और प्रत्येक प्रत्यक्ष रोजगार के लिए 6.1 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन दुनिया में सबसे बड़े रोजगार और आउटपुट देने वाले क्षेत्रों में से एक है।

पिछले 7 वर्षों में भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हुए बदलाव के बारे में बात करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता नागरिक उड्डयन बाजार है। देश में हवाई अड्डों की संख्या 2013-14 में 74 से बढ़कर लगभग 140 (हेलीपोर्ट और पानी के गुंबदों सहित) के साथ क्षेत्र में चतुर्दिक विस्तार हुआ है। इस संख्या के 2024-25 तक 220 तक जाने की संभावना है। उस समय देश में 400 विमान थे और 7 साल में यह संख्या बढ़कर 710 हो गई है। सरकार का यह इरादा है कि हर साल 100 से अधिक विमान शामिल हों। उन्होंने कहा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी (कोई जगह छूट न जाए) के प्रावधान के साथ सरकार का ध्यान रीजनल कनेक्टिविटी पर है। श्री सिंधिया ने कहा कि उड़ान (यूडीएएन) हर एक नागरिक को जोड़ने और आम आदमी के लिए उड़ानों को सुलभ बनाने का एक मिशन है। उन्होंने कहा कि, "हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहां में उड़ पाए।" उड़ान (यूडीएएन) योजना के लिए प्रधान मंत्री के विज़न को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 409 से अधिक मार्गों की पहचान की गई है, 1.75 लाख से अधिक उड़ानें हुई हैं और 91 लाख से अधिक यात्री लाभान्वित हुए हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि नागरिक उड्डयन परितंत्र में कार्गो, एमआरओ, एफटीओ, ग्राउंड हैंडलर, ड्रोन जैसे अन्य घटक शामिल हैं और इन सबके लिए आवश्यक काम किया जा रहा है। एमआरओ के लिए नई नीति की घोषणा की गई है। और अधिक प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं ताकि भारतीय पायलटों को देश के भीतर ही प्रशिक्षित किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय पायलटों में 15% महिला पायलट हैं, जो वैश्विक औसत का तीन गुना है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के लिए नई नीति की घोषणा कर दी गई है और पीएलआई योजना शुरू की गई है, ताकि भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक अगुवा बनाने के प्रधान मंत्री के सपने को साकार किया जा सके। श्री सिंधिया ने यह भी कहा कि नई हेलीकॉप्टर नीति की भी घोषणा की गई है।

नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल ने बताया कि भारत की उड़ान (यूडीएएन) योजना श्रेणी 3 और श्रेणी 4 शहरों तक पहुंच रही है, जिससे बड़ी संख्या में भारतीय लोग कहीं जाने के लिए हवाई यात्रा कर सकेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने लघु विमान उप-योजना का भी शुभारंभ किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य छोटे विमानों (समुद्री विमानों सहित) के माध्यम से संचालन पर विशेष ध्यान देने के साथ एक विकास-उन्मुख ढांचा बनाकर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुविधाजनक बनाना और इसे प्रोत्साहित करना है। यह योजना इस पहल की सफलता की दिशा में सहयोग करने के लिए राज्यों, एयरलाइंस, हवाईअड्डा ऑपरेटरों और नीति निर्माताओं जैसे प्रासंगिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करके देश में छोटे विमान संचालन के लिए एक परितंत्र के निर्माण की सुविधा प्रदान करने का इरादा रखती है।

श्री सिंधिया ने शैले (लकड़ी का बंगला) का दौरा किया और एयरफोर्स, सारंग टीम द्वारा एरोबेटिक्स का प्रदर्शन देखा।

श्री सिंधिया ने स्थिर प्रदर्शन क्षेत्र भी देखा जिसमें एयरबस 350 से लेकर छोटे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तक कई प्रकार के विमान दिखाई दिए।

केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें भाग लेने वालों में विमान और हेलीकॉप्टर निर्माता, एयरक्राफ्ट इंटीरियर्स, एयरक्राफ्ट मशीनरी और उपकरण कंपनियां, हवाईअड्डा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, ड्रोन, कौशल विकास, अंतरिक्ष उद्योग, एयरलाइंस, एयरलाइन सेवाएं और कार्गो शामिल हैं।

भारत को दुनिया का कंटेंट उपमहाद्वीप बनाने का लक्ष्य

अर्चिता ठाकुर

दुबई की अपनी यात्रा के तीसरे दिन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज दुबई एक्सपो 2020 स्थित इंडिया पवेलियन में 'भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग की वैश्विक पहुंच' पर अभिनेता श्री रणवीर सिंह के साथ बातचीत की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुबई में भारतीय लोग भारत के असली ब्रांड एंबेसडर हैं। 1.7 मिलियन दर्शकों के साथ इंडिया पवेलियन ने बड़ी तादाद में लोगों को आकर्षित किया है। मंत्री ने आगे कहा कि देश भारत की आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है और समारोह केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आयोजित हो रहे हैं। भारत के सॉफ्ट पावर बनने में फिल्मों के योगदान को स्वीकार करते हुए, केंद्रीय़ मंत्री ने कहा कि भारत कहानी कहने वालों की भूमि है और फिल्म उद्योग ने विदेश के लोगों को बहुत प्रभावित किया है, जो भारत को उसकी फिल्मों की वजह से पहचानते हैं। मंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य भारत को दुनिया का कंटेंट उपमहाद्वीप बनाना है। इससे भारत में लाखों नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं और पूरी दुनिया के लिए कंटेंट तैयार करने में मदद मिल सकती है। मंत्री ने विभिन्न फिल्मों में किए अभिनय को याद करते हुए श्री रणवीर सिंह को अभिनय प्रतिभा का पावरहाउस माना।

श्री रणवीर सिंह ने कहा कि भारतीय कंटेट वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कगार पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि भारतीय मनोरंजन दुनियाभर में तेजी से विस्तार कर रहा है। हमारी कहानियां लोगों से सीधे जुड़ती हैं और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर जाती है। इतना ही नहीं, विदेश में रहने वाले भारतीय फिल्मों के माध्यम से भारत के साथ जुड़ते हैं। इस दिलचस्प चर्चा से पहले केंद्रीय मंत्री ने श्री रणवीर सिंह के साथ दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन का दौरा किया। इससे पहले, दिन में केंद्रीय मंत्री ने दुबई पर्यटन और वाणिज्य विपणन निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसाम काजिम के साथ पर्यटन क्षेत्र के संबंध में दुबई को दुनिया का एक पसंदीदा पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की। बैठक के दौरान मंत्री ने एक्सपो के आयोजन के लिए दुबई की सराहना की, जो महामारी के बावजूद काफी सफल रहा है। दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर दुबई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि भारतीयों ने महामारी के वर्षों में लंदन जैसी पश्चिमी राजधानियों की बजाय दुबई के लिए उड़ान भरना पसंद किया।

श्री इसाम काजिम ने कहा कि एक निश्चित लक्ष्य के साथ निर्णायक नेतृत्व होने के कारण दुबई को यह सफलता हासिल हुई है। उन्होंने कोविड के दौरान दुबई अथॉरिटी की रणनीति के बारे में भी बात की, जब मार्च 2020 में शहर को बंद कर दिया था। अधिकारियों ने पूरी तरह से नई रणनीति अपनाई और प्रतिबंध व प्रोटोकॉल सुनिश्चित किए। यात्रियों के लिए टीकाकरण और पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिए गए थे और दुबई पर्यटकों के लिए खुलने वाला पहला शहर था।

श्री काजिम ने इस बात का उल्लेख किया कि दुबई 2025 तक 25 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करने और दुनिया का सबसे अधिक घूमा जाने वाला शहर बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यह शहर दुबई की मार्केटिंग जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है जिससे लोग आने में सहज महसूस करें और व्यवसायों को स्थापित करना आसान हो, दुबई को रहने के लिए सबसे अच्छे शहर के रूप में प्रचारित किया जाए, एफडीआई को बढ़ावा देने, टेक कंपनियों को न्योता देने, अमीरात एयरलाइंस के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास हो। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दुबई भी क्रिप्टो करंसी को लेकर तमाम विकल्पों पर विचार कर रहा है। हालांकि यह अभी जोखिम भरा और कानूनी रूप से वैध नहीं है।

श्री काजिम ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। भारत अपने प्रमुख शहरों/राज्यों के अनोखे पहलुओं का उपयोग करते हुए उनकी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके साथ ही भारत की आईटी प्रतिभा वैश्विक उद्योग को लाभान्वित करती है, जिसे सामर्थ्य के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है।

देवभूमि उत्तराखण्ड से होगी समान नागरिक संहिता की शुरुआत

विशेष संवाददाता

समान नागरिक आचार संहिता का मुद्दा आज एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल यह मुद्दा आज का नहीं है, यह अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नजरिये से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित में चिन्तन, निर्णय एवं क्रियान्वयन की अपेक्षा है। भले ही भाजपा के लिये यह चुनावी मुद्दा रहा हो, लेकिन इसको लागू करने की अपेक्षा सभी जाति, धर्म, वर्ग, भाषा के लोगों के हित में है। हां, इसे लागू करने का साहस एवं दूरदर्शिता भाजपा और उसके नेता प्रदर्शित कर रहे हैं, यह स्वागतयोग्य है। इसे मजहब या साम्प्रदायिकता की राजनीति से ऊपर उठ कर पूरे देश की सामाजिक समरसता के नजरिये से देखा जाना चाहिए। संवैधानिक दृष्टि से भी यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि भारत का संविधान धर्म या जाति-बिरादरी अथवा स्त्री-पुरुष या क्षेत्रीय पहचान की परवाह किये बिना प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार देता है। उत्तराखंड के पुनः मुख्यमन्त्री बने पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह राज्य में एक समान नागरिक आचार संहिता को लागू करने के अपनी पार्टी भाजपा के चुनावी फैसले को लागू करने का इरादा जाहिर किया है उसका देश के सभी राज्यों में बिना आग्रह, पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह के स्वागत किया जाना चाहिए।

भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ विभिन्न पंथों व पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। इन सबके शादी करने, बच्चा गोद लेने, जायदाद का बंटवारा करने, तलाक देने व तलाक उपरांत तलाकशुदा महिला के जीवनयापन हेतु गुजारा भत्ता देने आदि के लिए अपने-अपने धर्मानुसार नियम, कायदे व कानून हैं। इन्हीं नियमों, कायदे व कानूनों को पर्सनल लॉ कहते हैं। अंग्रेज जब भारत आए और उन्होंने यह विविधता देखी, तो उस समय उन्हें लगा पूरे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता बनानी आवश्यक है। जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो हर धर्मों के लोगों ने इसका विरोध किया। ऐसे में उन्होंने लम्बे समय तक यहाँ अपने पांव जमाये रखने के लिए किसी से उलझना ठीक नहीं समझा। इन परिस्थितियों में 1860 में उन्होंने इंडियन पैनल कोड तो लागू किया पर इंडियन सिविल कोड नहीं। यानि एक देश-एक दंड संहिता तो लागू की, लेकिन एक देश-एक नागरिक संहिता लागू करने का जिम्मेदारी एवं साहसपूर्ण काम नहीं किया। उसके बाद बनी सरकारों ने तो अंग्रेजों की सोच एवं नीतियों का ही अनुसरण किया, इसलिये उन्होंने भी अपने राजनीतिक हितों के लिये इसे लागू नहीं किया। जबसे नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने साहसिक निर्णय लेते हुए राष्ट्र को नया उजाला एवं सांसें दी हैं। भले

ही वह कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का साहसिक एवं सूझबूझ भरा निर्णय हो या तीन तलाक का मुद्दा।

कांग्रेस सरकारों ने हिन्दू एवं अन्य धर्मों को कमजोर करने एवं मुस्लिमों को संख्याबहुल बनाने के लिये अपने हित को सर्वोपरि माना। अपनी इन्हीं गलत नीतियों एवं संकीर्ण राजनीति के कारण कांग्रेस लगातार कमजोर होते होते अब एकदम रसातल में जा चुकी है। आजादी के बाद जिस तरह मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों को उनकी मजहब की पहचान के आधार पर उनके धार्मिक कानूनों को मान्यता देने का प्रावधान किया गया वह देश की आन्तरिक एकता व समरसता में व्यवधान पैदा करने वाला था। सभी मत-मजहब वालों के लिए तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, विवाह की आयु, बच्चों को गोद लेने और विरासत संबंधी नियम एक समान बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इन सभी मामलों में एक जैसे नियम बन जाते हैं तो समान नागरिक संहिता का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसकी शुभ शुरुआत देवभूमि से हो रही है, यह सुखद संकेत है।

तथ्य यह भी है कि गोवा में समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है और वहां सभी समुदायों के लोग रहते हैं। आखिर जो व्यवस्था गोवा में बिना किसी बाधा के लागू है, वह शेष देश में क्यों नहीं लागू हो सकती? प्रश्न यह भी है कि जब अन्य कई लोकतांत्रिक देशों में तुर्की, सूडान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, इजिप्ट और पाकिस्तान में समान नागरिक संहिता लागू है तो भारत में उसका विरोध क्यों होता है? देश के अनेक मुस्लिम संगठनों ने आजादी के आन्दोलन में सहयोग एवं सहभागिता ही नहीं की, बल्कि भारत के बंटवारे का विरोध भी किया था। लेकिन आजाद भारत में इन संगठनों ने भी कभी मुसलमानों को भारत की राष्ट्रीय धारा में मिलने की प्रेरणा नहीं दी और उनकी मजहबी पहचान को खास रुतबा दिये जाने की ही कोशिशें करते हुए सर्वाधिक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को इसके उपाय सुझाये। सबसे दुखद यह है कि 1947 में मजहब के आधार पर ही मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाये जाने के बावजूद हमने अपनी राष्ट्रीय नीति में परिवर्तन नहीं किया और इसके उलट उन्हीं प्रवृत्तियों व मानसिकता को मुल्ला-मौलवियों व मुस्लिम उलेमाओं की मार्फत संरक्षण दिया गया जिन्होंने भारत के बंटवारे तक में अहम भूमिका निभाई थी। जिसकी वजह से भारत में मुसलमानों की राजनैतिक पहचान एक 'वोट बैंक' के रूप में बनती चली गई और 'मुस्लिम तुष्टीकरण' का अघोषित एजेंडा चल पड़ा।

देश में मुसलमान लगातार बहुसंख्य बनने की ओर अग्रसर होता रहा और बहुसंख्य हिन्दू लगातार अल्पसंख्य होने की कगार पर अग्रसर होता रहा। सोचने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस ने भी मुसलमानों को वोट बैंक से अधिक नहीं समझा और अपने स्वार्थ के लिये उनका इस्तेमाल किया। इससे इस समुदाय के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिवेश हमेशा पिछड़ा ही रहा। अब मोदी सरकार न केवल इस वर्ग के लोगों का जीवनस्तर ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, बल्कि उन्हें उन्नत जीवनशैली भी दे रही है।

इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 494 के अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष एक विवाह के रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता। दूसरी ओर मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकता है। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के अनुसार तलाकशुदा पत्नी पति से आजन्म गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है। शाहबानो केस इसका उदाहरण है। इसी तरह बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के अनुसार बाल विवाह अपराध है, परन्तु मुस्लिम समाज के लिए यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ईसाई विवाह अधिनियम 1872, ईसाई तलाक अधिनियम 1869 भी पुराने हैं व हिन्दू विवाह अधिनियम से अलग हैं। ये विषमताएं देश की धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्नचिन्ह हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत का समान आचार संहिता पर बहुत ही तर्कसंगत दृष्टिकोण है। इस मुद्दे को लेकर संघ और भाजपा पर अत्यंत संकीर्ण, सांप्रदायिक और समाज-विरोधी दृष्टिकोण का आरोप लगता रहा है। जबकि मोहन भागवत का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है कि जो भारत में पैदा हुआ और जो भी भारत का नागरिक है, वह हिंदू है। हिंदू होने और भारतीय होने में कोई फर्क नहीं है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी मोहन भागवत की राय है कि सर्वसम्मति के बिना इसे लागू करना उचित नहीं होगा।

उत्तराखंड पूरे देश में 'देवभूमि' के नाम से जाना जाता है, यह अध्यात्म की अलौकिक भूमि है, जहां सद्भावना एवं सौहार्द इंसानों में ही नहीं, जीव-जंतुओं एवं पशु-पक्षियों तक में व्याप्त है। संकीर्णता से ऊपर उठ कर जो किसी भी व्यक्ति में ईश्वर की सर्व व्यापी निरंकार सत्ता का बोध कराती है। ईश्वर की पृथ्वी पर इस निकटता को केवल सनातन या हिन्दू दर्शन अथवा इस धरती से उपजे अन्य धर्म दर्शन ही बताते हैं। अतः बहुत आवश्यक है कि इस देवभूमि में सभी नागरिकों का आचरण एक समान ही हो और सभी के लिए सामाजिक नियम एक समान हों। वैसे गौर से देखा जाये तो 2000 में उत्तराखंड बनने से पहले और बाद में भी इसकी पर्वतीय जनसंख्या में खासा परिवर्तन आया है और पहाड़ों पर मुस्लिम जनसंख्या में खासा इजाफा हुआ है।

उत्तराखंड में मदरसों की संख्या तक में अभिवृद्धि हो रही है। जब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा तो देश सही मायने में धर्मनिरपेक्ष बनेगा। विभिन्न समुदायों के बीच एकता की भावना पैदा होगी। एक ही विषय पर कम कानून होने से न्यायतंत्र को भी फैसले देने में आसानी होगी। कई मुस्लिम देशों जैसे टर्की व ट्यूनिशिया आदि ने भी शरीयत से हटकर नागरिक कानून बनाये हैं। मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में आने व अपने सामाजिक उत्थान के लिए सरकार पर समान नागरिक आचार संहिता लागू करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। राजनीतिक दलों एवं विभिन्न राज्य सरकारों को भी मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक ना मानते हुए तुष्टीकरण की नीतियों से ऊपर उठ कर सामाजिक समरसता व हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करना चाहिए।

भारतीय राजनीति में तेजी से उभर रही आम आदमी पार्टी

विशेष संवाददाता

पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, गोवा तथा मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों में जहां पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर बोला है, वहीं अन्य चारों राज्यों में भाजपा दोबारा सरकार बना रही है। पंजाब के चुनाव में तो केजरीवाल की पार्टी 'आप' ने इतिहास रच डाला है। भले ही 'आप' का जादू उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश में नहीं चल सका लेकिन पंजाब के अलावा 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा चुनाव में भी दो सीटें जीतकर वह वहां भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुई है।

एक ओर जहां कांग्रेस, बसपा जैसे विपक्षी दलों को मतदाताओं ने कड़ा संदेश दिया है, वहीं राष्ट्रीय राजनीति में 'आप' के भाजपा के विकल्प के रूप में उभरने का मार्ग भी पंजाब के नतीजों के बाद प्रशस्त हुआ है। पंजाब में 'आप' की जिस तरह की आंधी चली और मतदाताओं

> उत्तर प्रदेश में पिछली बार के मुकाबले भाजपा गठबंधन को भले ही 50 के करीब सीटों का नुकसान हुआ लेकिन फिर भी भाजपा की उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों में धमाकेदार जीत ने देश की राजनीति में आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बदलावों के संकेत दे दिए हैं।

ने अन्य पार्टी के बड़े-बड़े सूरमाओं के मुकाबले केजरीवाल की पार्टी पर भरोसा जताया, उसके बाद आप भारत की राजनीति का तेजी से उभरता हुआ सितारा बन गई है।

इन विधानसभा चुनावों में एक और जहां उत्तर प्रदेश में कभी अपने ही बूते लगातार पांच साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व प्रदेश की राजनीति से करीब-करीब खत्म हो गया है, वहीं इन चुनावों में सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो है कांग्रेस पार्टी, जिसके समक्ष अब अपना अस्तित्व बनाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाये खड़ी है। दरअसल यह तय है कि अब पांच विधानसभा चुनावों में भी पार्टी की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर गांधी परिवार के प्रति विरोध बढ़ेगा और कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर पहले के मुकाबले और ज्यादा तेज होंगे। इसका स्पष्ट संकेत चुनावी नतीजों पर टिप्पणी करते हुए जी-23 के नेता मनीष तिवारी के उस बयान से भी लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह राहुल गांधी से ही पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की इस दुर्गति का असर महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखने को मिल सकता है।

उत्तर प्रदेश में पिछली बार के मुकाबले भाजपा गठबंधन को भले ही 50 के करीब सीटों का नुकसान हुआ लेकिन फिर भी भाजपा की उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों में धमाकेदार जीत ने देश की राजनीति में आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बदलावों के संकेत दे दिए हैं। उम्मीदों से परे भाजपा को मिली इस बड़ी चुनावी जीत के बाद देश में तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भाजपा से निपटना अब और भी बड़ी चुनौती होगा, वहीं इस जीत ने वैश्विक स्तर पर पहले से काफी मजबूत माने जाते रहे 'मोदी ब्रांड' को और मजबूत कर दिया है।

भाजपा के खिलाफ भले ही चुनाव में तमाम बड़े मुद्दे थे और कुछ जगहों पर सत्ता विरोधी लहर भी दिखाई दे रही थी लेकिन इसके बावजूद नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक सूझबूझ और रणनीति के चलते उनके जादू के समक्ष सब बेअसर साबित हुआ।

हालांकि अकेले होने के बावजूद अखिलेश यादव ने जाटों, अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ों के बीच अच्छा तालमेल बनाया था और उनकी प्रत्येक चुनावी सभाओं में उमड़ती भीड़ से चुनावी माहौल कुछ और ही कहानी कहता दिखता था लेकिन चुनावों ने स्पष्ट कर दिया कि चुनावों में जुटती भारी भीड़ किसी की जीत की गारंटी नहीं हो सकती। चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि किसानों की नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी, खेतों में फसलों को रौंदते जानवर जैसे कई बड़े मुद्दे कहीं पीछे छिपकर रह गए और अपनी चुनावी रणनीतियों की बदौलत इन तमाम मुद्दों के बावजूद भाजपा बड़ी आसानी से रिकॉर्ड बहुमत के साथ दोबारा उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना रही है।

भाजपा के बारे में यह विख्यात हो चुका है कि वह किसी भी चुनाव को जीतने के लिए अपनी चुनावी रणनीतियां बहुत पहले ही बना लिया करती है। वैसे भाजपा के पास चेहरे के अलावा संसाधन, संगठित कार्यकर्ताओं की मजबूत ताकत और आनुषंगिक संगठनों का सहयोग चुनावों में सोने पे सुहागा साबित हुआ है। चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में तीन कद्दावर मंत्रियों और करीब दर्जन भर विधायकों का विद्रोह भाजपा के लिए परेशानी का कारण बना था लेकिन आलाकमान ने चुनावी वैतरणी पार करने के लिए जिस तरह के समीकरण साधे, उससे विपक्ष के मंसूबों पर आसानी से पानी फिर गया।

किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, निःशुल्क गैस कनैक्शन, आयुष्मान भारत योजना के अलावा पिछले दो वर्षों से हर वर्ग के गरीबों को वितरित किए जा रहे निःशुल्क राशन जैसी योजनाओं ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को पीछे छोड़ दिया। भाजपा नेता स्वयं यह स्वीकारने से गुरेज नहीं कर रहे कि मुफ्त राशन वितरण योजना पार्टी के लिए गेमचेंजर साबित हुई है। भाजपा ने इन चुनावों में उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड जैसे राज्यों में जातियों की राजनीति के तिलिस्म को तोड़ने में भी सफलता हासिल की है और भाजपा की प्रचण्ड जीत ने यह तय कर दिया है कि इन राज्यों में अब जातिगत राजनीति की जगह धार्मिक पहचान की राजनीति तेजी से परवान चढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो पूरे 37 वर्षों के बाद भाजपा ऐसी पार्टी के रूप में उभरी है, जो पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरे कार्यकाल में सत्ता में वापसी कर रही है। भाजपा की इस बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के भीतर बहुत बड़ा हो गया है। कहा जाने लगा है कि लोकप्रियता के मामले में वह अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद भाजपा के दूसरे सबसे बड़े और ताकतवर नेता बन गए हैं और निश्चित रूप से इस रिकॉर्ड जीत के बाद अब उन्हें पार्टी के भीतर मिलने वाली चुनौतियां कुंद पड़ जाएंगी। चार राज्यों में भाजपा की जीत के बाद भाजपा गठबंधन की अब कुल 18 राज्यों में सरकारें हो गई हैं, जिनमें 12 राज्यों में भाजपा के ही मुख्यमंत्री हैं और भाजपा का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले 11 राज्य विधानसभा चुनावों पर रहेगा, जिनमें से गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं जबकि शेष राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे। चार राज्यों में भाजपा की जीत और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने संघ परिवार को योगी आदित्यनाथ के रूप में भाजपा तथा हिन्दुत्व का नया नेता दे दिया है और अब माना जाने लगा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों और उससे पहले होने वाले सभी चुनावों में संघ परिवार योगी आदित्यनाथ को देशभर में हिन्दुत्व के नए नेता के रूप में पेश करेगा।

बहरहाल, भाजपा की यह जीत जहां आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी, वहीं यह लोकसभा चुनावों की बुनियाद भी तैयार करेगी। कुल मिलाकर ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी बड़ा सबक हैं कि उन्हें अब केवल क्षेत्रीय अस्मिता और जातीय गौरव से अलग हटकर मुद्दों की राजनीति करनी होगी।

52 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास

विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान पंजेहड़ा में 225 करोड़ रुपये लागत की 52 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। इसके उपरान्त, पंजेहड़ा के शोभा माजरा में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने रामशहर में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामशहर को स्तरोन्नत कर 50 बिस्तर का करने, रामशहर में अग्निशमन उप-केन्द्र खोलने और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नालागढ़ को 200 बिस्तर के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने अन्धरोला में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने, डोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा पंजेहड़ा स्वास्थ्य उप-केन्द्र को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करने की भी घोषणा की। क्षेत्र में आज किए गए 225 करोड़ रुपये के उद्घाटन एवं शिलान्यास यह दर्शाते हैं कि प्रदेश सरकार ने सदैव ही इस क्षेत्र के विकास का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में 5.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बस अड्डा राज्य के सबसे बड़े बस अड्डों में से एक है और इससे यहां बसों का सुगम परिचालन सुनिश्चित होगा। इस परियोजना के लिए समस्त बजट प्रावधान वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा ही किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने गत वर्ष दिसम्बर माह में अपना चार वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ राज्य का पहला ऐसा क्षेत्र रहा है, जहां से पिछले लोकसभा चुनावों में 40 हजार से अधिक की बढ़त प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कोरोना वैक्सीन जैसे संवेदनशील मामले पर भी केवल राजनीति ही की है। उन्होंने कहा कि राज्य में आज 50 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र हैं जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में इनकी संख्या केवल दो थी। महामारी के प्रारम्भ में राज्य में केवल 50 वेंटीलेटर थे, जबकि आज प्रदेश में एक हजार से अधिक वेंटीलेटर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं द्वारा 53 लाख से

अधिक मास्क तैयार कर जरूरतमंदों में निःशुल्क वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर ने इस स्थिति को सम्भालने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई स्वदेशी वैक्सीन के कारण ही आज देश और प्रदेश इस स्थिति से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम हो सका है। जय राम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अपना आधार खो चुकी है और प्रदेश में भी यह पूरी तरह से धड़ों में बंटी हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस केवल दो सीटें ही जीत पाई जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को दर्शाता है और देश के लोगों द्वारा कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना से वर्तमान में 7.50 लाख लाभार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस पर 1300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार बजट दस्तावेजों के साथ प्रथम बार जेंडर बजट स्टेटमेंट भी प्रस्तुत की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आगंनवाड़ी सहायिकाओं, आशा वर्कर, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड-डे मील वर्कर, जलवाहकों, जलरक्षक, मल्टी पर्पज वर्कर, पैराफिटर और पम्प ऑपरेटरों के मासिक मानदेय में आशातीत बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय कर गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त निःशुल्क सिलेण्डर प्रदान किए जाएंगे। हिमकेयर योजना के अन्तर्गत अब तीन वर्षों तक पंजीकरण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि दिहाड़ादारों की दिहाड़ी में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 350 रुपये प्रतिदिन किया गया है। शगुन योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवार की बेटी को उसके विवाह पर 31 हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले 20 हजार गौवंश को गौ सदनों एवं गौ अभयारण्यों में पहुंचाया गया है। जय राम ठाकुर ने नालागढ़ में 5.60 करोड़ रुपये लागत से निर्मित नए बस अड्डा भवन, 57 लाख रुपये लागत के जैव-विविधता वन एवं इसकी मोबाइल ऐप्लीकेशन, नालागढ़ शहर के लिए 20 करोड़ रुपये लागत की मल निकासी योजना, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्याल नालागढ़ में 7.21 करोड़ रुपये लागत से निर्मित बहुद्देशीय हॉल व महाविद्यालय के लिए 1.46 करोड़ रुपये लागत के अतिरिक्त भवन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्तरोन्नत विभिन्न सड़कों जिनमें 9.76 करोड़ रुपये लागत की बरूना-करसोली सड़क, 3.02 करोड़ रुपये लागत की अन्दोरला ऊपरला से झाजरा सड़क, 4.30 करोड़ रुपये लागत की रेडू-झिरीवाला-भागंला सड़क तथा 5.84 करोड़ रुपये लागत की मांगता-प्लासी-माजरा सड़क, नाबार्ड के अन्तर्गत 2.86 करोड़ रुपये लागत की राजपुरा धागं ऊपरली धागं नेहली सड़क एवं चिकनी खड्ड पर निर्मित पुल, मंझोली चान्दपुर सड़क पर खानन खड्ड पर 75 लाख रुपये लागत से निर्मित पुल, ग्राम पंचायत बवासनी के लोधीवाला, बिसैण चमारण और कटल गांवों के सम्पर्क मार्ग पर चिकनी खड्ड (नदी) पर 71 लाख रुपये लागत से निर्मित पुल, कानणी से बिसैण चमारण काटलू पहाड़ी चिकनी सड़क पर 72 लाख रुपये लागत से चिकनी खड्ड पर निर्मित पुल, ग्राम पंचायत डोली और सौर के मध्य गम्बर खड्ड पर 1 करोड़ 42 लाख रुपये लागत के पैदल पुल और 81 लाख रुपये लागत से निर्मित राष्ट्रीय उच्च मार्ग-105 पर टीवीएस फैक्ट्री झिरीवाला से धूंधली सम्पर्क मार्ग का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने रामशहर और नालागढ़ तहसील के ग्राम समूह के लिए 4.44 करोड़ रुपये लागत से निर्मित उठाऊ जलापूर्ति योजना रामशहर के संवर्धन कार्य, नालागढ़ क्षेत्र में द्वितीय चरण में खरूनी, रिया, कल्याणपुर गुज्जरां, अन्देरली भटौली, कालीबाड़ी, अभिपुर, तनरियां गुज्जरां और कोटला पलाही के लिए 4.29 करोड़ रुपये लागत से निर्मित सात टय्बैल, नालागढ़ क्षेत्र में चरण एक में हातरा, कोठेवाली, रतेपुर, रामपुर गुज्जरां, कश्मीरपुर गुज्जरां, राजपुरा और निचली मलवाणा में 4.55 करोड़ रुपये लागत से निर्मित सात टय्बैल, नालागढ़ तहसील में 90 लाख रुपये लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना बरूना के उन्नयन, नालागढ़ तहसील में 1.41 करोड़ रुपये लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना भोगपुर भंगलान के संवर्धन कार्य और इसी तहसील के बगलेहड़ में 12.18 करोड़ रुपये लागत से निर्मित 66/33/11 केवी, 1ग्20 एमवीए उपकेन्द्र का भी लोकार्पण किया।

जय राम ठाकुर ने नालागढ़ तहसील में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास भी किए, जिनमें 1.48 करोड़ रुपये से कीरपालपुर उठाऊ जलापूर्ति योजना के रेट्रोफिटिंग और उन्नयन कार्य, 4.83 करोड़ रुपये से जल शक्ति अनुभाग नालागढ़ के अन्तर्गत विभिन्न उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं के रेट्रोफिटिंग व उन्नयन कार्य, 2.24 करोड़ रुपये लागत की उठाऊ जलापूर्ति योजना राख घंसोट, सौरी भूमियां चुगुवाल, नालागढ़ के धरोहर किला के समीप 1.87 करोड़ रुपये लागत के चेकडैम, नालागढ़ शहर के लिए 22.07 करोड़ रुपये से उठाऊ जलापूर्ति योजना के संवर्धन कार्य, 11.82 करोड़ रुपये से पनोह बारियां अलयोण दानोघाट पक्के सम्पर्क मार्ग और अलयोण खड्ड पर पुल निर्माण, 3.88 करोड़ रुपये लागत से बैहली से देवली पक्के सम्पर्क मार्ग और कल्याणपुर-देयोली खड्ड पर पुल निर्माण, नाबार्ड के अन्तर्गत 3.93 करोड़ रुपये से बेघड़ी काठीवाला गड़ामोड़, 10.09 करोड़ रुपये से तमरोह पहरूड़ वैद का जोहार चानोबरी नवांगर अम्बवाला सड़क के मेटलिंग व टारिंग कार्य, 7.43 करोड़ रुपये लागत के धेरोवाल से घियार औद्योगिक सड़क, मंझोली लखनपुर सड़क पर कहाना खड्ड पर 2.75 करोड़ रुपये लागत के पुल, निकुवाल मण्डयारपुर सड़क पर सिरसा नदी पर 5.05 करोड़ रुपये लागत के पुल नालागढ़ में 12.15 करोड़ रुपये लागत के ग्रामीण आजीविका केन्द्र और खेड़ा निचला घराट से दादा कानिया सड़क खिरा खड्ड पर 55 लाख रुपये लागत से निर्मित होने वाला पुल शामिल है।

मुख्यमंत्री ने नालागढ़ तहसील में 2.06 करोड़ रुपये लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ जलापूर्ति योजना कंगनवाल एवं धागं ऊपरली, 2.24 करोड़ रुपये लागत से जल शक्ति अनुभाग पंजेड़ा के अन्तर्गत विभिन्न उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं के रेट्रोफिटिंग और उन्नयन

कार्य, 1.15 करोड़ रुपये लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना छरोली ब्राहमणा के रेट्रोफिटिंग एवं उन्नयन कार्य, 1.34 करोड़ रुपये लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना राजपुरा के संवर्धन एवं उन्नयन कार्य, जल शक्ति अनुभाग रामशहर के अन्तर्गत 1.63 करोड़ रुपये लागत से विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के रेट्रोफिटिंग और उन्नयन कार्य, ग्राम पंचायत धबोटा में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 90 लाख रुपये लागत की उठाऊ जलापूर्ति योजना लखनपुर झिरन/उठाऊ जलापूर्ति योजना माजरा, जल शक्ति अनुभाग जोघोन/मिटियां बैहली, खलेड़ और इसके समीपवर्ति गावों की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के 7.25 करोड़ रुपये लागत के रेट्रोफिटिंग और उन्नयन कार्य, रामशहर तहसील में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 85 लाख रुपये लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना सुना बडखोया के रेट्रोफिटिंक व उन्नयन कार्य और नालागढ़ तहसील में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 55 लाख रुपये लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना चनोबरी लेहरी के रेट्रोफिटिंग एवं उन्नयन कार्य का भी शिलान्यास किया।

जय राम ठाकुर ने तहसील नालागढ़ में 85 लाख रुपये से उठाऊ जलापूर्ति योजना खैरा चैक की रेट्रो फिटिंग और सुधार कार्य, तहसील राम शहर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 42 लाख रुपये से उठाऊ जलापूर्ति योजना जगलोग कनोइला की रेट्रो फिटिंग और सुधार कार्य तहसील राम शहर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 40 लाख रुपये से उठाऊ जलापूर्ति योजना धर्मांणा की रेट्रो फिटिंग और सुधार कार्य, तहसील नालागढ़ में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 40 लाख रुपये से उठाऊ जलापूर्ति योजना कुलारी पडयाना की रेट्रो फिटिंग और सुधार कार्य, तहसील राम शहर में जल शक्ति अनुभाग नंद में 69 लाख रुपये से जल आपूर्ति योजना की रेट्रो फिटिंग और सुधार कार्य, 3 करोड़ रुपये से उठाऊ जलापूर्ति योजना भोगपुर भगलान के संवर्धन और सुधार कार्य, तहसील नालागढ़ की ग्राम पंचायत बवासनी में 87 लाख रुपये से उठाऊ जलापूर्ति योजना गोयला पनेर के संवर्धन और राम शहर तहसील के समीपवर्ती गांवों के लिए 17.86 करोड़ रुपये से उठाऊ जलापूर्ति योजना नंद, उठाऊ जलापूर्ति योजना रजवां रंधाला, बहाव जल आपूर्ति योजना डोली, बहाव जल आपूर्ति योजना, जंजली के जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर क्षेत्र के विकास कार्यो के प्रति हमेशा ही गंभीर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश का निर्बाध विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बनने वाले मेडिकल डिवाइसिज़ पार्क से क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में चार राज्यों में हुए चुनावों में जीत दर्ज कर भाजपा ने पुनः अपनी सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि ट्रक संचालकों की जुर्माना माफ करने की मांग पर प्रदेश सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

मारवाह स्टूडियोज में नम आंखों से याद किया गया "शहीदी दिवस"

नोएडा में मारवाह स्टूडियोज के प्रागंण में भारत के क्रांतिकारी वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 91वीं पुण्यतिथि शहीद भगत सिंह फोरम के अंतर्गत मनाई गई। इस मौके पर भगत सिंह के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का न केवल जिक्र हुआ बल्कि उनकी फांसी दिए जाने वाले दिन को नम आंखों से याद किया गया। इस मौके पर ए ए एफ टी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर और शहीद भगत सिंह फोरम के अध्यक्ष डॉ संदीप मारवाह ने कहा की " महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जितना याद किया जाए उतना कम है। उनकी याद में हम कितने भी आंसू बहाए कम हैं। उन्होंने वतन के लिए जो किया है इसके लिए उन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा।"

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्य सभा सासंद, रामचंद्र जागंड़ा जी ने कहा की सवाल ये उठता हैं की कैसे बेखौफ होकर अंग्रेज हमारे वीर सपूतों को फांसी दे पाए? क्यों तमाम विदेशी आक्रांता भारत में आए और मार काट करते हुए लूटकर चलते बने? आखिर क्या कारण रहा की हमने नौ सौ सालों की गुलामी झेली" इसके बाद उन्होंने अपने वक्तव्य में परत दर परत बातें खोली और भारत उन दिनों के इतिहास से परिचित कराया। कार्यक्रम में सम्मिलित वक्ताओं में नोएडा के पूर्व चेयरमैन श्री देवदत्त शर्मा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अभय सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर, श्रीमती नरेश मुदगिल और ऑब्जर्वर डॉन के संयुक्त संपादक एवम नागरी लिपि परिषद के मीडिया प्रभारी दिनेश गौड़ समेत सभी ने अपने अपने विचारों से अवगत कराया। शहीद भगत सिंह फोरम के महासचिव सुशील भारती ने कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरोया और तीनों क्रातिकारियों के जीवन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र किया। कार्य क्रम के अंत में शहीद भगत सिंह फोरम के अध्यक्ष डॉ संदीप मारवाह ने सभी वक्ताओं और प्रतिभागियों को फोरम की सदस्यता से नवाजा।

टूटते-झड़ते बालों की समस्याओं के घरेलू उपाय

विशेष संवाददाता

आजकल की बदलती जीवनशैली, खानपान की आदतों, बढ़ते प्रदूषण और धूल-मिट्टी के कारण बालों की तमाम समस्याएँ होने लगती हैं। आज के समय में हर कोई बालों की किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है। लेकिन बालों के झड़ने की समस्या से अधिकतर लोग परेशान हैं। वैसे तो बाजार में कई एंटी-हेयरफॉल शैंपू मौजूद हैं। लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स से बालों को लंबे समय में नुकसान होता है। ऐसे में आप झड़ते बालों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों की मदद ले सकते हैं। इन उपायों से आपके बालों के झड़ने की समस्या दूर होगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी-

बालों के लिए नारियल का तेल बहुत फायदेमंद होता है। इससे बालों को पोषण मिलता है और बाल घने और मजबूत बनते हैं। अगर बालों के झड़ने से परेशान हैं तो नारियल के तेल से अपने सिर की मालिश करें।

बालों को झड़ने से रोकने के लिए शहद और अंडे की जर्दी के मिश्रण से सिर की मालिश करें। अंडे में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, जिससे बालों को पोषण मिलता है। इससे बालों का झड़ना कम होता है और बाल घने और मजबूत बनते हैं।

झड़ते बालों की समस्या के लिए कपूर और नारियल के तेल का इस्तेमाल बहुत कारगर घरेलू नुस्खा है। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर सिर की मालिश करने से टूटते-झड़ते बालों की समस्या दूर होती है।

बालों को साफ करने के लिए आंवला, शिकाकाई पाउडर में दही मिलकर एक मिश्रण तैयार कर लें। इस मिश्रण को लगाने से स्कैल्प के रोमछिद्रों में जमा गंदगी साफ होती है। इसके साथ ही यह बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है।

नींबू ना केवल बालों से रूसी को दूर करने में मदद करता है। बल्कि यह बालों की ग्रोथ बढ़ाने में भी बहुत फायदेमंद है। झड़ते बालों की समस्या से छुटकारा पाना के लिए बालों को नींबू के रस से धोएं।

बालों का झड़ना रोकने के लिए दही, नींबू और सरसों के तेल को मिलाकर इस पेस्ट को अपने सिर पर लगाएं। 30 मिनट के बाद धो लें। इस पेस्ट के इस्तेमाल से आपको टूटते बालों और गंजेपन की समस्या से छुटकारा मिलेगा।

बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त फूड्स जैसे मछली, सोयाबीन, अंडे और बीन्स आदि का सेवन करना चाहिए।

योग के जरिए भी आप टूटते-झड़ते बालों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बालों के झड़ने से रोकने के लिए कुछ योगसा काफी फायदेमंद होते हैं। इससे सिर और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। घने, लंबे और मजबूत बालों के लिए रोजाना शीर्षासन और सर्वांगासन जैसे आसन करें।

वैसे तो बाजार में कई एंटी-हेयरफॉल शैंपू मौजूद हैं। लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स से बालों को लंबे समय में नुकसान होता है। ऐसे में आप झड़ते बालों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों की मदद ले सकते हैं। इन उपायों से आपके बालों के झड़ने की समस्या दूर होगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी

बदरीनाथ धाम में मौजूद है यह बेहद पवित्र झरना, पाप करने वाले लोग छू तक नहीं पाते हैं इसका पानी

विशेष संवाददाता

'देवभूमि' कहा जाने वाला उत्तराखंड राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक महत्व के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यहां ऐसे कई स्थल हैं जिनका विशेष धार्मिक महत्व है। उत्तराखंड में कई बेहद खूबसूरत झरने हैं, जहां दुनियाभर से पर्यटक लुत्फ उठाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी झरने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आज हम आपको वसुंधरा झरना के बारे में बताने जा रहे हैं जो पवित्र बद्रीनाथ धाम से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना अपने आप में बहुत रहस्यमई है उसके बारे में कहा जाता है कि इस झरने का पानी पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरता।

हर व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरता है झरने का पानी : वसुंधरा झरना करीब 400 फीट ऊंचाई से गिरता है। इस झरने का पानी जमीन पर गिरते समय मूर्तियों के समान नजर आता है। यह झरना बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका पानी हर व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरता है। माना जाता है कि इसका पानी पापी लोगों पर नहीं गिरता। देश विदेश से लोग इस झरने और इसके चमत्कार को देखने आते हैं।

यहाँ सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे : इस झरने को लेकर कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। एक धार्मिक कथा के अनुसार यहां पांच पांडवों में से सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। कहा जाता है कि अगर इस झरने का पानी आप पर गिरे तो समझ जाएं कि आप नेक हैं। यही वजह है कि दुनियाभर से पर्यटक यहां आते हैं और इस झरने के नीचे खड़े होते हैं।

झरने के पानी में पाए जाते हैं कई औषधीय गुण : यह भी कहा जाता है कि इसने का पानी कई जड़ी बूटी वाले पौधों को छूकर नीचे गिरता है इसलिए इस पर भी इस झरने का पानी पड़ता है वह हमेशा के लिए निरोगी हो जाता है। अगर आप भी बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो वसुंधरा झरना देखना ना भूलें। इस जगह की खूबसूरती आपको स्वर्ग में होने की अनुभूति करवाएगी।

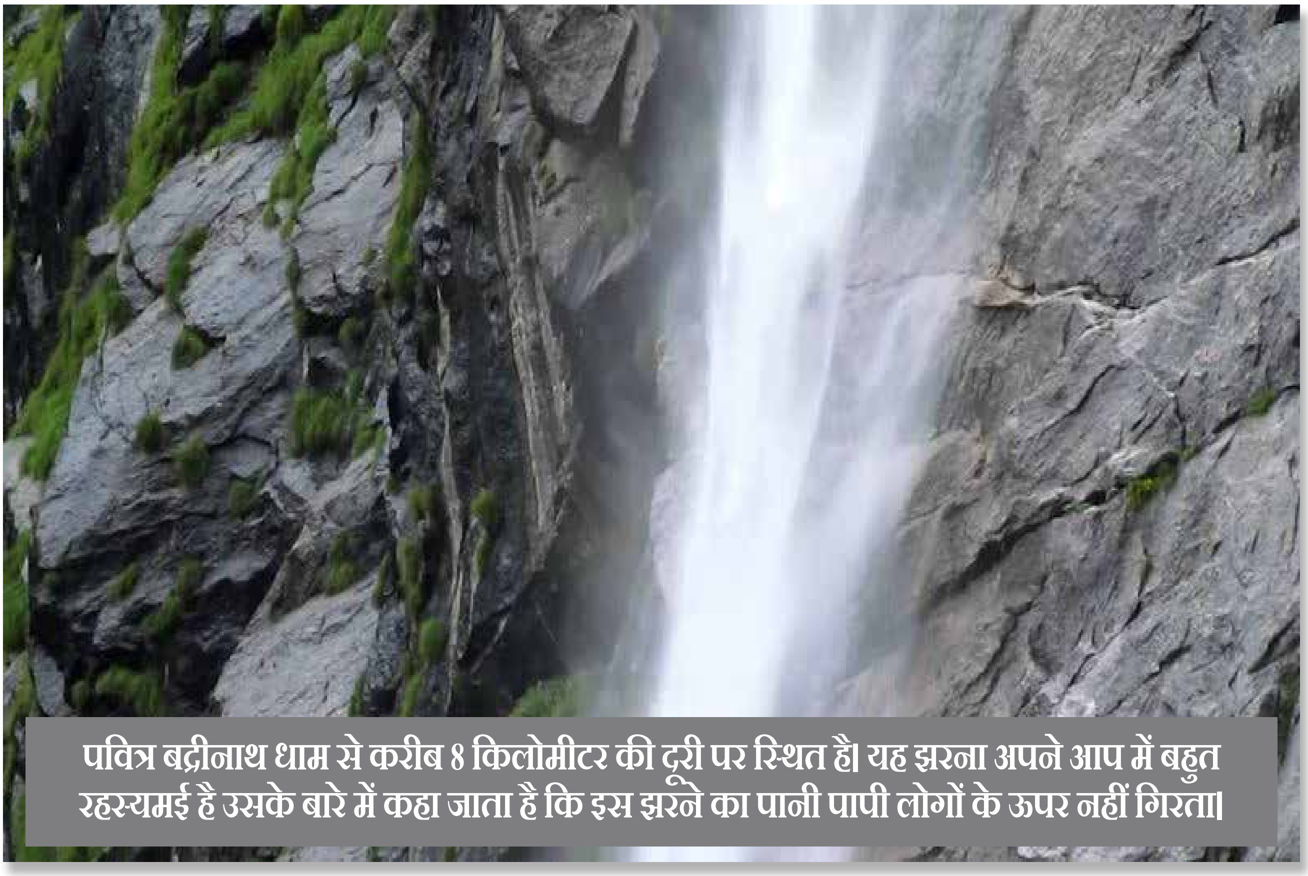

पवित्र बद्रीनाथ धाम से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना अपने आप में बहुत रहस्यमई है उसके बारे में कहा जाता है कि इस झरने का पानी पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरता।

तरबूज है सेहत का खजाना, इसके ये हैं 8 चमत्कारी फायदे

विशेष संवाददाता

जैसे कि हम सब जानते हैं कि तरबूज गर्मियों का सबसे पौष्टिक फल माना जाता है. तरबूज में 92% पानी और 8% शुगर होती है. जैसे कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तो ये शरीर में पानी की कमी को भी पूरी करने में सहायता करता है. तरबूज विटामिंस का भी अच्छा स्रोत माना जाता है जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी 6, आदि. यह हमारी कोशिकाओं की रिपेयरिंग के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें बीटा – कैरोटीन मौजूद होता है. रिसर्च के अनुसार तरबूज वजन कम करने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और यह हमारी त्वचा, बाल, और आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है. तरबूज हमारे शरीर में पानी की कमी को दूर करता है. तरबूज पेट के कैंसर, मधुमेह, और हृदय रोग से भी बचाता है. ज्यादातर लोग तरबूज खाने के समय उसके बीज को निकाल देते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तरबूज के बीजों में बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं तरबूज के दोनों काले और सफेद बीज खाने के लिए सुरक्षित और फायदेमंद होते हैं.

तरबूज खाने के बाद हमें क्या नहीं खाना चाहिए?

अब हम बात करेंगे कि तरबूज खाने के बाद या तरबूज खाने के साथ-साथ हमें क्या ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन तरबूज खाने के बाद नहीं खाना चाहिए .

1. वैज्ञानिकों के मुताबिक तरबूज में 92% से 96% पानी होता है जो कि हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है.अगर हम तरबूज खाने के बाद पानी का सेवन करेंगे तो यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक साबित होगा.

2. जिन लोगों को अस्थमा और त्वचा से संबंधित कोई बीमारी हो उन लोगों को तरबूज खाने से बचना चाहिए क्योंकि तरबूज ठंडा होता है और यह सांस की नली में सूजन पैदा कर सकता है साथ ही से छींक की समस्या भी बढ़ जाती है.

3. तरबूज अगर चावल या दही खाने के बाद खाया जाए तो वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित होगा.

4. तरबूज कभी भी सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए. क्योंकि तरबूज को खाली पेट खाने से हमें उल्टी अथवा पेट से संबंधित और कई समस्याओं की सामना करना पढ़ सकता है.

5. तरबूज को ज्यादा मात्रा में खाने से हाइपरक्लेमिया की शिकायत हो सकती है जिसमें पोटेशियम की मात्रा सामान्य से ज्यादा हो जाती है इससे दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं.

6. तरबूज खाने के बाद हमें शराब नहीं पीनी चाहिए या फिर जो लोग शराब पीते हैं उन्हें तरबूज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तरबूज में लाइकोपिन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से लीवर में सूजन होने की संभावना रहती है.

7. तरबूज खाने के आधे घंटे बाद तक कुछ ना खाने का प्रयास करें क्योंकि इसमें बहुत जादा मात्रा में ग्लूकोस होता है. यह तुरंत एनर्जी देता है और उसको पचने में कम से कम आधा घंटा काफी होता है.

तो ये थी वो चीजें जिनको तरबूज खाने के बाद खाने से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हो सकता है कि आप इन चीजों का सेवन करते हों और आपको लगता है कि यह नुकसान तो नहीं करती तो इससे क्या फर्क पड़ता है लेकिन अब आप जान गए हैं तो इन चीजों का साथ में सेवन करने से जरूर बचें क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक बात होगी.

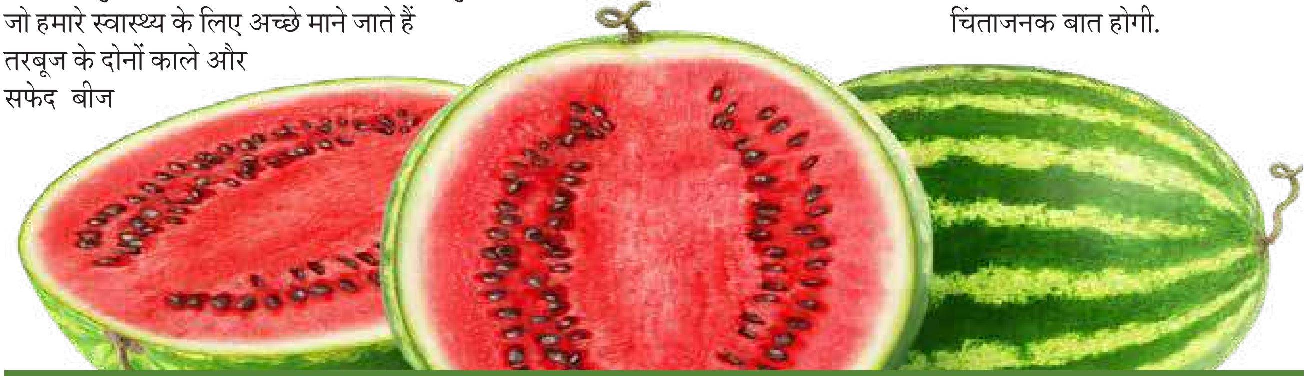

ठंडा, मीठा रसीला तरबूज खाने से शरीर में ताजगी आ जाती है।क्या आप जानते हैं कि तरबूज स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी खजाना है। जी हां, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम और एंटी ऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तरबूज के सेवन से स्वास्थ्य को कई फायदे होते हैं और कई बीमारियां दूर होती हैं।

सामाजिक विषयों पर बनी फिल्में राष्ट्र निर्माण में दे रही योगदान

समाज की बेहतरी, भलाई और मानवता का स्पंदन ही भारतबोध का सबसे प्रमुख तत्व है। फिल्म क्षेत्र में भारतीय विचारों के लिए यही कार्य 'भारतीय चित्र साधना' जैसी समर्पित संस्था विगत कई वर्षों से कर रही है। भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित 'चित्र भारती फिल्मोत्सव 2022' का आयोजन इस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 25 से 27 मार्च तक किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं को कला जगत और खासकर फिल्मों के क्षेत्र में अवसर, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज का सिनेमा पश्चिम की नकल कर रहा है, जबकि भारतीय चित्र साधना भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाले सिनेमा पर कार्य कर रहा है। भारतीय सिनेमा का इतिहास भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक मूल्यों और संवेदनाओं का ऐसा इंद्रधनुष है, जिसमें भारतीय समाज की विविधता, उसकी सामाजिक चेतना के साथ सामने आती है। भारतीय समाज का हर रंग सिनेमा में मौजूद है। भारत में अलग-अलग समय में अलग तरह की फिल्मों का निर्माण किया गया। 1940 की फिल्मों का दशक गंभीर और सामाजिक समस्याओं से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर फिल्मों के निर्माण का समय था। 1950 का दशक फिल्मों का आदर्शवादी दौर था। 1960 का वक्त 1950 के दशक से काफी अलग था। राज कपूर ने जो रोमांटिक फिल्मों का ट्रेंड शुरू किया था, वह इस दौर में अपने पूरे शबाब पर था। 1970 का दशक व्यवस्था के प्रति असंतोष और विद्रोह का था। 1980 का फिल्मों का दशक यथार्थवादी फिल्मों का दौर था, जबकि 1990 का वक्त आर्थिक उदारीकरण का था।

भारतीय सिनेमा में जनमानस और भारतबोध के आधार पर फिल्मों का निर्माण करने की परंपरा बहुत पुरानी है। बॉलीवुड का सिनेमा भारतीय समाज की कहानी को कहने का सशक्त माध्यम रहा है। इसके जरिए भारत की स्वतंत्रता की कहानी, राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के संघर्ष की कहानी और वैश्विक समाज में भारत की मौजूदगी की कहानी को चित्रित किया जाता रहा है। भारतीय सिनेमा विदेशों में काफी कामयाब

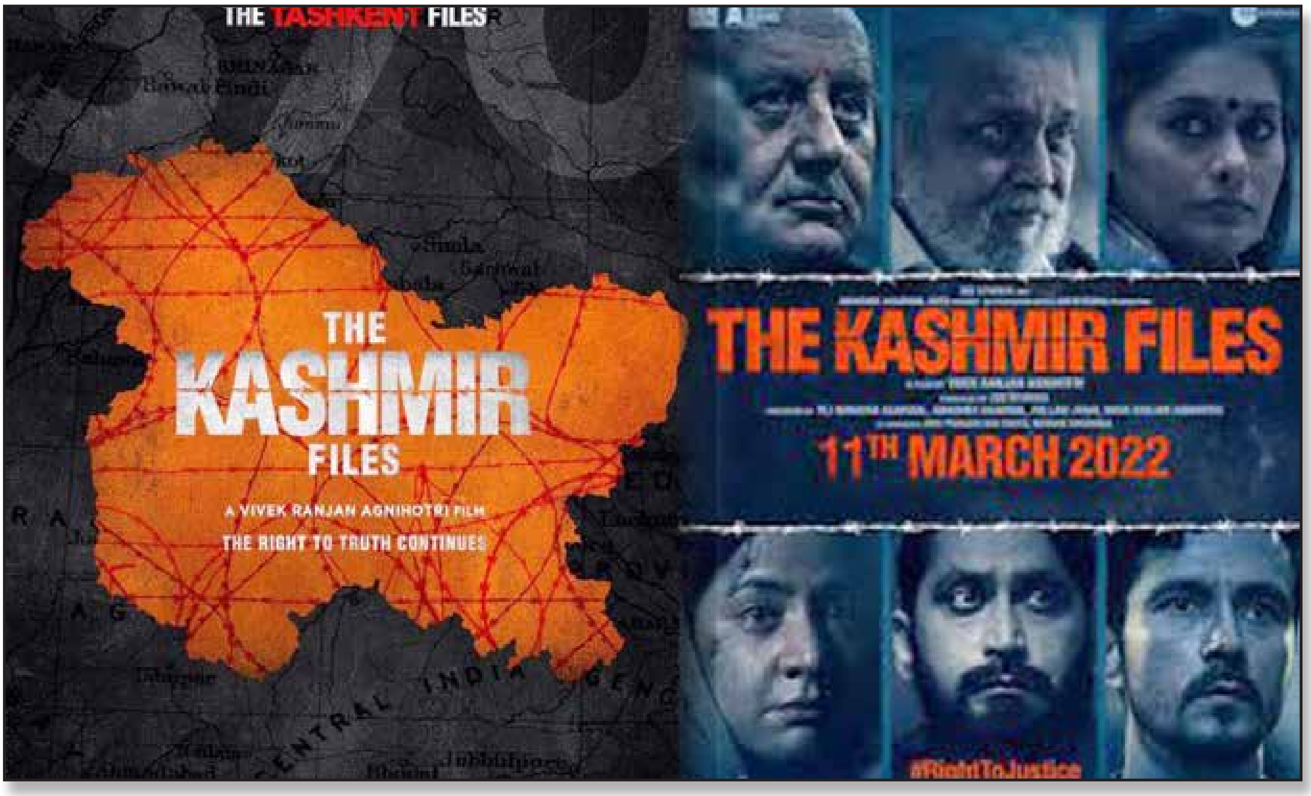

हुआ है और इसके जैसा दूसरा कोई ब्रांड नहीं जो दुनिया भर में इतना कामयाब हुआ है। भारतीय सिनेमा में बदलते भारत की झलक भी मिलती रही है। 1943 में बनी फिल्म 'किस्मत' उस दौर में सुपर हिट साबित हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जब चरम पर था, तब इस फिल्म का एक गाना बेहद लोकप्रिय हुआ था, 'दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तां हमारा है।'

1949 में भारत को स्वतंत्रता मिले कुछ ही वक्त हुआ था। देश के तौर पर हमारी पहचान बस बन रही थी। तब 'शबनम' नामक फिल्म में पहली बार विविधभाषाई गीत का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बंगाली, मराठी और तमिल भाषा का उपयोग किया गया था। इसके जरिए दर्शकों को ये बताने की कोशिश की गई थी कि ये सभी भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं। मशहूर फिल्मकार वी. शांताराम 1921 से 1986 के बीच करीब 65 साल तक फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहे। उन्होंने 1953 में विविध रंगी और बहुभाषी समाज होने के बाद भारत की एकता के मुद्दे पर 'तीन बत्ती चार रास्ते' फिल्म बनाई। इस फिल्म की कहानी में एक ऐसा परिवार था, जिसके घर की वधुएं अलग-अलग भाषाएं बोलती हैं।

1960 में के. आसिफ ने अकबर की बादशाहत पर 'मुगल-ए-आजम' के तौर पर एक भव्य और ऐतिहासिक फिल्म बनाई', जबकि उसी वक्त राजकपूर 'जिस देश में गंगा बहती है' और दिलीप कुमार 'गंगा-जमुना' जैसी फिल्में बना रहे थे। 1981 में प्रदर्शित मनोज कुमार की फिल्म 'क्रांति' ने भारतबोध के एक नए युग की शुरुआत की। 2001 में आमिर खान की फिल्म 'लगान' में भारत के एक गांव के किसानों को अपनी लगान की माफी के लिए अंग्रेजों के साथ क्रिकेट मैच खेलते हुए दिखाया गया। इस मैच में भारतीय गांव के किसानों ने अंग्रेजों को हरा दिया। ये विश्वस्त भारत की तस्वीर थी, जो अपने उपनिवेशवाद के दिनों को नए ढंग से देख रहा था। इसके अलावा भूमंडलीकरण और तेजी से बदलते महानगरीय समाज, खासकर महिलाओं की स्थिति को फिल्मों में दिखाया गया। ऐसी फिल्मों की शुरुआत 1994 में प्रदर्शित फिल्म 'हम आपके हैं कौन' से हुई।

भारत के सॉफ्ट पावर की शक्ति में हमारी फिल्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये फिल्में ही हैं, जो पूरे विश्व में भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय फिल्में भारतीयता का आईना रही हैं। दुनिया को भी वो अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। हमारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचाती रहती हैं, साथ ही पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाने, भारत को ब्रांड बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सिनेमा की एक साइलेंट पावर ये भी है कि वो लोगों को बिना बताए, बिना ये जताए कि हम आपको ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं; एक नया विचार जगाने का काम करता है। अनेक ऐसी फिल्में होती हैं, जिन्हें173 देखकर जब लोग निकलते हैं, तो अपने जीवन में कुछ नए विचार ले करके निकलते हैं।

भारतीय फिल्मों में आज दिख रहा बदलाव सिर्फ स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्मों जैसा भव्य नहीं है, बल्कि यह एक सौंदर्यशास्त्रीय बदलाव है, जो बदल रहा है, उभर रहा है और अपनी स्वतंत्र राह पकड़ रहा है। इन दिनों शौचालय जैसा विषय हो, महिला सशक्तिकरण जैसा विषय हो, खेल हों, बच्चों की समस्याओं से जुड़े पहलू हों, गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता का विषय हो या फिर हमारे सैनिकों का शौर्य, आज एक से एक बेहतरीन फिल्में बन रही हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' इस कड़ी का सबसे ताजा उदाहरण है। इन फिल्मों की सफलता ने सिद्ध किया है कि सामाजिक विषयों को लेकर भी अगर बेहतर विजन के साथ फिल्म बने, तो वो बॉक्स ऑफिस पर भी सफल हो सकती है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी दे सकती है।

सोमी ने ऐश्वर्या राय को लेकर किया बड़ा खुलासा

सोमी अली 90 के दशक में कुछ बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रही हैं, जिनमें कृष्ण अवतार, अंत, आंदोलन और माफिया शामिल हैं। सोमी अली को लेकर अफवाह थी कि वह सलमान खान के साथ लंबे समय तक रिश्ते में थी लेकिन कुछ सालों बाद दोनों का रिश्ता टूट गयी था क्योंकि दोनों में से कोई भी इस रिश्ते में खुश नहीं था। बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस सोमी अली ने इंस्टाग्राम पर 'बॉलीवुड के हार्वे विंस्टीन' को बेनकाब करने की चेतावनी देते हुए एक पोस्ट डाली है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन का उल्लेख किया है और दावा किया है कि फन्ने खां अभिनेत्री भी गाली-गलौज का शिकार हो चुकी हैं।

सोमी अली ने इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड के एक गाने की एक तस्वीर साझा की, जिसमें दो अभिनेताओं के सिल्हूट दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, "बॉलीवुड के हार्वे वेनस्टेन! आप बेनकाब हो जाएंगे। जिन महिलाओं को आपने गाली दी है, वे एक दिन सामने आएंगी और अपनी सच्चाई साझा करेंगी। बिल्कुल ऐश्वर्या राय बच्चन (@aishwaryaraibachchan_arb) की तरह। उन्होंने सीधे व्यक्ति का नाम लेने से परहेज किया।

सोमी अली ने इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड के एक गाने की एक तस्वीर साझा की, जिसमें दो अभिनेताओं के सिल्हूट दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, "बॉलीवुड के हार्वे वेनस्टेन! आप बेनकाब हो जाएंगे। जिन महिलाओं को आपने गाली दी है, वे एक दिन सामने आएंगी और अपनी सच्चाई साझा करेंगी।

सोमी अली 90 के दशक में कुछ बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रही हैं, जिनमें कृष्ण अवतार, अंत, आंदोलन और माफिया शामिल हैं। कई साक्षात्कारों में उन्होंने खुलासा किया है कि वह बॉलीवुड में सिर्फ सलमान खान के साथ रहने के लिए आई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने मैंने प्यार किया देखी थी और सलमान खान से शादी करना चाहती थी। मैं सलमान खान की तस्वीर अपने पर्स में रखती थी। सलमान और सोमी 1991 से 1999 तक रिलेशनशिप में थे। उनके ब्रेकअप के बाद, उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग छोड़ दिया। हाल ही में जूम डिजिटल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'मुझे सलमान खान से ब्रेकअप किए 20 साल हो चुके हैं। उसने मुझे धोखा दिया और मैं उससे नाता तोड़ कर चली गया। यह इतना सरल है। मैं वहां (भारत) शुरू में बॉलीवुड का हिस्सा बनने के लिए कभी नहीं गयी। एक बार जब मैंने अपने पूर्व के साथ संबंध तोड़ लिया, तो मुझे वहां वापस जाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा था।

प्रेग्नेंट देबिना बनर्जी ने अनारकली सूट में बिखेरे जलवे

सब टीवी के मशहूर शो 'चिड़िया घर' में मयूरी की भूमिका निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाली टेलीविज़न अभिनेत्री देबिना बनर्जी इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी की वजह से सुर्खियों में छायी हुईं हैं। अभिनेत्री शादी के 10 साल बाद माँ बनने वाली हैं और अपनी प्रेगनेंसी को खुलकर एन्जॉय कर रहीं हैं। प्रेग्नेंट देबिना अपने इंस्टाग्राम के जरिये फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। अभिनेत्री की यह तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं। अभिनेत्री देबिना बनर्जी इस समय प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में हैं और हाल ही में उनकी गोदभराई की रस्म हुई। गोदभराई की रस्म की तस्वीरें देबिना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने गोदभराई के बारे में बताया और लिखा, "मैं पहले से ही एक कंपनी महसूस कर रही हूँ।" इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में अभिनेत्री ने अपने लुक के बारे में बात करते हुए लिखा, "हालाँकि मैं अधिक बंगाली दिखना चाहती थी पर आखिर में बिहारी या फिर उत्तर भारतीय जैसी दिख रही हूँ।"

गोदभराई के कार्यक्रम में अभिनेत्री ने लाल रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था। ट्रेडिशन ऑउटफिट के साथ अभिनेत्री ने ट्रेडिशनल जेवेलरी और लाइट मेकअप से अपने लुक को कम्पलीट किया था। अनारकली सूट में देबिना अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुईं बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। हजारों लोग अभिनेत्री की खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठे हैं और कमेंट सेक्शन में अभिनेत्री को बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा देबिना ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे गाने अरबी कुथु पर डांस भी किया। इसका वीडियो भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अभिनेत्री देबिना बनर्जी अपनी प्रेगनेंसी पीरियड को जमकर एन्जॉय कर रही हैं। देबिना के पति और अभिनेता गुरमीत चौधरी एक अच्छे पति की तरह अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखे रहे हैं।

आपको बता दें कि अभिनेत्री देबिना बनर्जी ने अभिनेता गुरमीत चौधरी के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उनसे साल 2011 में शादी कर ली थी। देबिना और गुरमीत टेलीविज़न जगत के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं और दोनों के चाहने वाले भी बहुत हैं। दोनों मिलकर सोशल मीडिया पर अपनी फनी वीडियोज अपलोड करके फैंस को हँसाते रहते हैं।

'माई' नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज

नेटफ्लिक्स ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज माई का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। यह एक सस्पेंस-थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे अनुष्का शर्मा के भाई कर्णेश शर्मा की प्रोडक्शन कम्पनी क्लीन स्लेट्ज ने प्रोड्यूस किया है। अनुष्का ने कुछ दिनों पहले ही इस प्रोडक्शन कम्पनी से अलग होने का एलान किया था। माई में साक्षी तंवर मुख्य भूमिका में हैं, जबकि राइमा सेन और वामिका गब्बी समेत कई जाने-माने चेहरे अहम भूमिकाओं में दिखेंगे।

साक्षी एक ऐसी मां की भूमिका में हैं, जो अपनी बेटी के कातिलों की तलाश में निकली है। उसे इस सवाल का जवाब चाहिए कि उसकी बेटी को आखिर क्यों मारा गया? ट्रेलर की शुरुआत में दिखाते हैं कि बेटी बनी वामिका गब्बी को एक ट्रक साक्षी की आंखों के सामने रौंदते हुए निकल जाता है। बेटी के कातिलों की तलाश करते हुए साक्षी को धमकियां मिलती हैं। उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। जानलेवा हमले किये जाते हैं। ट्रेलर कहानी के लिए उत्सुकता जगाने में कामयाब रहता है और सीरीज के लिए बेकरारी बढ़ाता है।

साक्षी तंवर इस सीरीज में एक ऐसी मां की भूमिका में हैं जो अपनी बेटी के कातिलों की तलाश में निकली है। सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज में राइमा सेन और वामिका गब्बी भी अहम किरदारों में नजर आएंगी।

ट्रेलर में साक्षी बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आती हैं। उनके कैरेक्टर की कई परतें हैं। साक्षी ने अब तक जितने किरदार निभाये हैं, यह उन भूमिकाओं से अलग है। साक्षी इससे पहले ऑल्ट बालाजी की कर ले तू भी मोहब्बत, जी5 की द फाइनल कॉल और ऑल्ट बालाजी-जी5 की मिशन ओवर मार्स वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं। साक्षी अब डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी की फिल्म पृथ्वीराज में एक भूमिका में दिखेंगी, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में हैं। इससे पहले द्विवेदी की फिल्म मोहल्ला अस्सी में साक्षी ने सनी देओल के किरदार की पत्नी का किरदार निभाया था। वहीं, वामिका डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज ग्रहण से चर्चा में आयी थीं और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई फिल्म 83 में भी वो एक किरदार में नजर आयी हैं।

पॉलिटिकल ट्रस्ट

हिन्दी मासिक

सदस्यता फार्म

पॉलिटिकल ट्रस्ट के सदस्य बनने के लिए आपका सादर धन्यवाद।

नामः ....

पताः ....

.... मोबाईल ....

ई-मेलः ....

ऑर्डर फार्म			
	मासिक	20 रूपये	☐
	द्विमासिक	40 रूपये	☐
	त्रिमासिक	55 रूपये	☐
	अर्द्धमासिक	110 रूपये	☐
	वार्षिक	200 रूपये	☐

कृप्या ऑर्डर फार्म को भर कर उसका सदस्यता शुल्क पॉलिटिकल ट्रस्ट (Political Trust) के नाम पर चैक या डी.डी. माध्यम से नीचे दिए गए पते पर भेंजे।

पॉलिटिकल ट्रस्ट, एफ–92, टॉप फ्लोर, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली - 110095।

पॉलिटिकल ट्रस्ट
महिलाएं और पुरुष एक नई जागृति के अग्रदूत : राम नाथ कोविन्द
पॉलिटिकल ट्रस्ट
उम्मीद से अर्थव्यवस्था
पॉलिटिकल ट्रस्ट
डीएनए बोले तो हिंदुस्तान
पॉलिटिकल ट्रस्ट
गोवा
सपनों का शहर
पॉलिटिकल ट्रस्ट
हिंदी मासिक
पॉलिटिकल ट्रस्ट
यूपी में चुनाव को लेकर भाजपा ले सकती है बड़े फैसले
पॉलिटिकल ट्रस्ट
सरकार और जनता के बीच बढ़
पॉलिटिकल ट्रस्ट
COVID-19 vaccine
वैक्सीन के साथ सावधानी जरूरी
पॉलिटिकल ट्रस्ट
पॉलिटिकल ट्रस्ट
खुशहाल किसान समृद्ध मध्यप्रदेश